खंड: 7, अंक: 10 अक्टूबर 2024 RNI- DELHIN/2021/84711

ISSN- 2584-2803 (Print)

संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

चुनाव विज्ञान बनाम चुनाव परिणाम: हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर चुनाव विश्लेषण

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

दिल्ली विश्वविद्यालय

संपादक

प्रोफेसर सुनील कुमार

निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: director@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://cgs.du.ac.in/directorMessage.html

संपादक मंडल

डॉ रमेश कुमार भारद्वाज

सहायक आचार्य, सरकारी पी.जी कॉलेज, जीवाजी विश्वविद्यालय, श्योपुर पाली रोड, मध्य प्रदेश, पिन कोड-476337
संयुक्त निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: rkbhardwaj1@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.mphighereducation.nic.in

डॉ महेश कौशिक

सहायक आचार्य, श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: mkaushik@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.aurobindo.du.ac.in

डॉ संध्या वर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: sverma@shyamlale.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://shyamlale.du.ac.in/wp-content/uploads/2021/11/sandhya-Verma-Political-Science.pdf

डॉ अभिषेक नाथ

सहायक आचार्य, एमएलटी कॉलेज, सहरसा; बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार।

ई-मेल आई डी: tuesdaytrack@gmail.com

प्रोफाइल लिंक: https://bpsm.bihar.gov.in/Assets2022/AssetDetails.aspx?P1=2&P2=12&P3=239&P4=3

© सीजीएस2024

संश्लेषण

चुनाव विज्ञान बनाम चुनाव परिणामः हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर चुनाव

अनुक्रमिका

संपादकीय

1. हरियाणा की चुनावी राजनीति का परिवर्तनीय स्वरूपः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
   – पंकज 1–6
2. भारत में चुनाव शास्त्र विश्लेषणः हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर चुनाव अध्ययन
   – विकास यादव 7–10
3. संख्याओं के परे सच्चाईः जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव का विश्लेषण
   – शशांक आचार्य 11–20
4. हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर में चुनाव विज्ञान व चुनाव परिणामों का तुलनात्मक विश्लेषण
   – नीलम 21–25
5. हरियाणा और जम्मू–कश्मीर चुनाव विश्लेषणः चुनाव विज्ञान का एक अध्ययन
   – कमल कुमार हुड्डा 26–31
6. जम्मू कश्मीर के चुनावी राजनीति: एक अध्ययन – हिताक्षी गिल 32–36
7. चुनाव विज्ञान बनाम चुनाव परिणामः हरियाणा एवं जम्मू–कश्मीर चुनाव विश्लेषण
   – आस्था सेहरावत 37–43
8. महिलाओं की चुनावी राजनीति में बढ़ती भूमिका – एलिन 44–48
9. चुनाव विज्ञान बनाम चुनाव परिणामः पूर्वानुमान या यथार्थता? – हितेन्द्र बारगल
   – प्रियंका बारगल 49–53

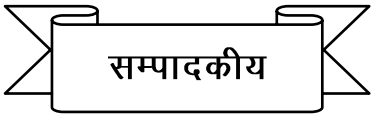

सम्पादकीय

निरंतरता, गुणवत्ता एवं महत्ता पर केन्द्रित सामरिक वाद–विषयों पर युवा शोधार्थियों से लेख आमंत्रण एवं प्रकाशन समसामयिक सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। प्रकाशन के इन महत्वपूर्ण सरोकारों और चुनौतियों के आलोक में वैश्विक अध्ययन केंद्र अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के 75वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा है। पाँच वर्षों से प्रकाशन की इस अकादमिक यात्रा में केंद्र एक परिवार के रुप में समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों से सामाजिक विज्ञान के प्रति अपने संकल्पित ध्येय को साकार करता आ रहा है। निरंतरता की इस कडी में संश्लेषण का यह अंश शोध के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एवं दृढ़निश्चतता को प्रदर्शित करने का ही एक सामान्य प्रयास है।

वर्ष 2024 को भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक चुनावी वर्ष के रुप में संबोधित किया जा सकता है। चुनाव विज्ञान और चुनाव परिणामों के मध्य संबंध प्रायः रुचिकर अंतदृष्टि प्रस्तुत करते हैं, विशेषकर जब सैद्धांतिक पूर्वानुमानों की तुलना वास्तविक परिणामों से की जाती है। हरियाणा और जम्मू–कश्मीर चुनावों का विश्लेषण इस विभाजन को उजागर करता है।

हरियाणा में, किसी विशेष पार्टी की ओर झुकाव वाले पूर्वानुमानों के बावजूद, अभियान के दौरान मतदाताओं की भावनाओं में अत्यधिक परिवर्तन आया, जिससे स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों की अपील व अंतिम समय के निर्णयों के जटिल अंतर्संबंध का पता चला। इसी प्रकार, जम्मू और कश्मीर के चुनाव परिणामों ने मतदान डेटा के आधार पर कुछ प्रत्याशित परिणामों का खंडन किया, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता, सुरक्षा चिंताओं और बदलती मतदाता वफादारी ने अंतिम परिणामों को आकार दिया। ये परिणाम प्रदर्शित करते हैं कि चुनाव विज्ञान मूल्यवान अंतदृष्टि प्रदान कर सकता है, किंतु यह राजनीतिक परिदृश्यों की अप्रत्याशित प्रकृति को पूरी तरह से समझ नहीं सकता है, जो प्रायः वास्तविक समय की घटनाओं व अंतिम समय के चुनावी बदलावों से प्रभावित होते हैं।

चुनाव विज्ञान और चुनाव परिणामों के मध्य यह विसंगति हमें याद दिलाती है कि यद्यपि वैज्ञानिक मॉडल रुझानों को समझने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं, किंतु वे किसी भी चुनाव में सक्रिय सूक्ष्म, गतिशील शक्तियों का स्थान नहीं ले सकते।

यह चुनाव 2024 भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। परिणाम न केवल तत्काल राजनीतिक रूपरेखा निर्धारित करेंगे अपितु आने वाले वर्षों में राज्यों के विकास व शासन के लिए दिशा भी निश्चित करेंगे।

राज्योय स्तर पर विषय की महत्ता तथा राज्य स्तर पर विमर्श की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने 'चुनाव विज्ञान बनाम चुनाव परिणामः हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर चुनाव विश्लेषण' विषय पर लेख आमंत्रित किये। नां उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य के बहुआयामी विषयों को भी संबोधित करते हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करने का एक सर्वनिष्ठ प्रयास, प्रयत्न और परिणाम है।

संपादक मंडल बृहस्पतिवार, 14 नवंबर 2024

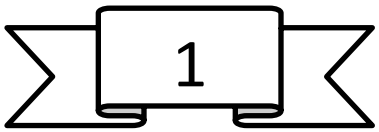

हरियाणा की चुनावी राजनीति का परिवर्तनीय स्वरूपः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

पंकज

अतिथि सहायक प्राध्यापक, देशबंधु महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

हरियाणा की चुनावी राजनीति ऐतिहासिकता का विश्लेषण किया जाये तो यह ज्ञात होता है कि यह निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। परंतु राज्य की चुनावी राजनीति का दलीय स्वरूप का प्रतिरूप एक ही रहा है। किंतु 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव ने दलीय स्वरूप को पूर्णतरू परिवर्तित कर दिया है क्योंकि हरियाणा की चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पहला ऐसा दल बन गया है जो लगातार तीसरी बार सत्तारूढ़ दल के रूप में उबारा है। इससे पूर्व कोई भी दल इस कीर्तिमान को अर्जित नहीं कर पाया था। राज्य की चुनावी राजनीति का यह परिवर्तनीय स्वरूप मात्रा चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवेश के परिवर्तनीय स्वरूप ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हरियाणा की चुनावी ऐतिहासिकता का अध्ययन किया जाये तो मुख्यतः चार निर्धारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं– प्रथम जातीय विभेदन, द्वितीय धार्मिक विच्छेदन, तृतीय डेरा व्यवस्था एवं चतुर्थ ग्राम्यीकरण। इन सभी निर्धारकों का व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाये तो यह प्रतीत होता है कि ये सभी निर्धारक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। राज्य का परिवर्तनीय सामाजिक परिवेश राज्य चुनावी राजनीति में नये प्रतिरूप और स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सभी निर्धारकों का व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन इस प्रकार है–

- जातीय विभेदनः प्रभुत्व से लोकतंत्रीकरण की ओर

चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से हरियाणा राज्य जाति की राजनीति का अध्ययन किया जाये तो यह तीसरे दौर में प्रवेश कर चुकी है। प्रथम, कालखंड में हरियाणा की चुनावी राजनीति पर जाट जाति का प्रभुत्व रहा है। राज्य स्तरीय नेतृत्व, प्रतिनिधित्व और मतदाताओं के हितों तक केवल जाट जाति का प्रतिनिधित्व और प्रभुत्व परिलक्षित होता था। हरियाणा राज्य में 11 बार जाट जाति

से मुख्यमंत्री बना है। 1966 से लेकर 2014 तक राष्ट्रीय दलों विशेषकर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की राजनीति जाटों के इर्द–गिर्द घूमती रही है। इस कालक्रम में जाट जाति के प्रभुत्व के निम्न कारण थे। प्रथम, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जाटों का प्रभुत्व था। आर्थिक क्षेत्र में जाट जमीदार कृषि व भूमि पर सामंती नियंत्रण स्थापित होंने के कारण अन्य पिछडी एवं दलित जातियां जाटों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर थी। इसी प्रकार हरियाणा का सामाजिक ढांचे में उच्च जातियां विशेष कर ब्राह्मण– बनिया आरंभ से ही कमजोर स्थिति में रहे। इसी कारण सामाजिक परिवेश पर जाटों का प्रभुत्व कायम रहा। द्वितीय, संख्याबल चुनावी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जाट जाति राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत है, जो अन्य जातियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तृतीय, राज्य की राजनीति ऐतिहासिकता भी जाटों के प्रभुत्व को कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य के औपनिवेशिक इतिहास का अध्ययन किया जाये तो ज्ञात होता है कि सर छोटूराम के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी का हरियाणा क्षेत्र में प्रभाव रहा है। राज्य के औपनिवेशिक नेतृत्व को औपनिवेशिक सरकार का संरक्षण प्रदान था। इसी वजह से राज्य के संसाधनों का जाट जाति के पक्ष में अधिक हस्तांतरण हुआ। जो उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व को कायम करने में सहायक रही।

1990 के चुनावी राजनीति ने जाति विभेदन को नया स्वरूप प्रदान करने में चौधरी भजनलाल के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। जाति आधारित सामाजिक एकजुट का उत्तर उनके द्वारा गैर–जाट आधारित सामाजिक गठजोड़ से दिया गया। हालांकि चौधरी भजनलाल इसका लाभ नहीं उठा पाये। क्योंकि इस समय गैर–जाट जाति में जातीय जागरूकता शैशवकाल में थी। जातीय जागरूकता गैर–जाट उच्च जातियों तक ही सीमित रही। गैर–जाट जाति आधारित गठजोड़ का सबसे अधिक प्रभाव 2014 और 2019 के चुनाव में देखने को मिलता है। इन दोनों चुनाव में भारतीय जनता पाटी (भाजपा) के द्वारा गैर–जाट नेतृत्व के रूप में मनोहर लाल खट्टर जो पंजाबी जाति से आते हैं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया। गैर–जाट गठजोड़ के कारण भाजपा हरियाणा में सहयोगी दल से सत्तारूढ़ दल में परिवर्तित हो गयी। गैर–जाट जातियों की एकजुटता के निम्न कारण थे। प्रथम, राज्य में भाजपा ही केवल एकमात्र ऐसा दल था जिसने गैर–जाट नेतृत्व को बढ़ावा दिया। कांग्रेस एवं क्षेत्रीय दलों में मुख्य नेतृत्व जाट जाति से संचालित था। इसके साथ ही एक लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति जाटों के इर्द–गिर्द घूमती रही जिसमें आमजन मानस जाटों के वैकल्पिक अन्य जातियों से नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहते थे।

वर्तमानकाल में हरियाणा की चुनावी राजनीति में जातीय विभेदन तृतीय चरण में प्रवेश कर चुका है। भाजपा के द्वारा अपनी जाति आधारित रणनीति में परिवर्तन करते हुए पिछड़ी और दलित जातियों विशेषकर वाल्मीकि, धानक, गडरिया आदि को अपने पक्ष में लामबंद किया है। पिछड और दलित जातियों को चुनावी लामबंद करने के लिये भाजपा ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया। भाजपा की जातीय रणनीति में नयापन लाने में निम्न कारण है। प्रथम, गैर– जाट जातीय गठजोड़ पर आधारित चुनावी रणनीति से आकस्मिक व अल्पकालीन सफलता ता मिल सकती है, परंतु दीर्घकाल तक गैर– जाट जातियों संगठि रखना कठिन है। इसके विपरीत पिछडी और दलित जातियां परआधारित गठजोड़ दीर्घकाल के लिए कायम रहने की संभावना अधिक है। इसके अलावा 2014 से ही पिछडी व दलित जातियों का समर्थन भाजपा को एक तरफा मिलते आया है। परंतु समर्थन के अनुसार प्रतिनिधित्व नेतृत्व नहीं मिल पा रहा था। इसलिए भाजपा ने इन जातियों को नेतृत्व देकर अपनी मजबूरी को मजबूती में परिवर्तित कर दिया है।

- धार्मिक विच्छेदन से धार्मिक जुड़ाव

हरियाणा की राजनीति में धार्मिकता का प्रभाव अलग पंजाब राज्य बनने के पश्चात् बहुत कम हो गया था क्योंकि राज्य की लगभग 90% जनसंख्या हिंदू धर्म से संबंधित थी। इसलिए जाति आधारित राजनीति प्राथमिक भूमिका में आ गयी। हरियाणा में धार्मिकता का पुनः उद्भव 1990 के पश्चात होता है। राम मंदिर के संघर्ष को लेकर राज्य में धार्मिक जागरूकता तो आयी। परंतु सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित रही। परंतु राजनीति में धार्मिकता का प्रभाव 2009–10 के पश्चात दक्षिणी हरियाणा जिले विशेषकर गुरुग्राम, नूंह, फरीदाबाद और पलवल में देखने को मिलता है। गौ– हत्या सार्वजनिक स्थानों व सड़कों पर नमाज को लेकर विवाद ने हिंदू समाज में धार्मिक अस्मिता को जागृत किया। जिसका प्रभाव 2014 के चुनाव में प्रदर्शित हुआ। भाजपा राज्य में सहयोगी दल से सत्तारूढ़ दल में परिवर्तित हो गयी। वर्तमानकाल में हरियाणा राज्य की राजनीति में धार्मिकता का प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। नूंह में हिंदू शोभा यात्रा, हिंदुओं का मेवात क्षेत्र से पलायन, कुछ जिलों विशेषकर फरीदाबाद, पलवल और मवात में परिवर्तित जनसंख्या समीकरण, लव जिहाद, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का बसना आदि धार्मिक विषय निरंतर हिंदू अस्मिता को चुनौती प्रदान कर रहे हैं। 1966 से राज्य की राजनीति धार्मिक विच्छेदन में धार्मिक जुड़ाव की ओर अग्रसर हो चुकी है।

- डेरा और खाप पंचायतः वर्चस्व से पतन की ओर

हरियाणा के सामाजिक परिवेश में आरंभ से ही डेरा और खाप पंचायत का विशेष महत्व रहा है और राज्य की राजनीति को प्रभावित करने में मुख्य निर्धारक के रूप में कार्य करती रही है। डेरा और खाप व्यवस्था राज्य की सामाजिक व्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता को निरंतर खोती जा रही हैं। डेरा व्यवस्था के सामाजिक परिवेश में प्रभाव कम होने के निम्न कारक उत्तरदायी है। प्रथम, डेरा व्यवस्था हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में उभरी थी। परंतु वर्तमानकाल में अंधविश्वास, विलासिता और आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन गई है। डेरा सच्चा सौदा के संचालक गुरमीत राम रहीम का आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। द्वितीय, राज्य सामाजिक व्यवस्था में नई धार्मिकता का जन्म हो रहा है। जिसने डेरा के प्रभाव को कमजोर किया है। हिंदू धर्म गुरुओं ने धार्मिक परंपराओं को परिवर्तित करते हुए निम्न जाति समुदाय के लोगों को अपने भक्त बनना प्रारंभ कर दिया है। जिससे हिंदू धर्म में मुख्य देवी– देवताओं की आराधना पूजा आदि फिर से आरंभ हुई है। माता की चौकी और माता का जागरण आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं।

डेरा व्यवस्था को कमजोर करने में जहां नयी धार्मिकता ने मुख्य योगदान दिया है वहीं खाप पंचायतों के कमजोर होने का मुख्य कारण राज्य की परिवर्तित सामाजिक– आर्थिक ढांचा है। राज्य की आर्थिक व्यवस्था समयानुसार गहरे एवं बड़े परिवर्तन से गुजरती आई है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि (21%) का योगदान निरंतर कम हो रहा है, जबकि औद्योगिक (28%) और सेवा क्षेत्र (51%) योगदान में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित सामंतवादी संबंध पूंजीवादी व भौतिकवादी संबंधों में परिवर्तित हो रहे है। जिससे खापां की स्थापित सामाजिक व्यवस्था इसके कारण कमजोर हो गई है। आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव राज्य राजनीति में भी देखने को मिलता है। दलों और नेताओं की चुनावी आर्थिक सहयोग के लिए निर्भरता खापों पर निरंतर कम होती जा रही है और इसका स्थान बड़े पूंजीपतियों ने ले लिया है। अतः खाप और डेरा व्यवस्था का सामाजिक परिवेश में कम होता प्रभाव ने राज्य की राजनीति में नये स्वरूप और प्रतिरूप को जन्म दिया है।

- ग्राम्यीकरण से शहरीकरण की ओर

हरियाणा की राजनीति अपने प्रारंभिक चरण में ग्रामीण जनसंख्या के हितों पर केंद्रित थी। परंतु वर्तमानकाल में हरियाणा राज्य ग्राम्यीकरण से शहरीकरण की ओर अग्रसर है। 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की लगभग 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी। जबकि 2011 की जनगणना में यह घट कर 65% पर आ गई थी। वर्तमानकालीन परिस्थितियों में अनुमान लगाया

जाये तो ग्रामीण जनसंख्या 60% से भी काम रह गयी है। जो राज्य में शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। शहरीकरण केवल आवासीय स्थितियां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने ग्रामीण स्तरीय सामुदायिक संस्कृति को भी कमजोर किया है। खान–पान, रहन–सहन इत्यादि आदतों में गहरा परिवर्तन आया है। शहरी संस्कृति के बढ़ते प्रभावों ने व्यक्तिवादी और भौतिकतावादी जीवन क्रिया को बढ़ावा दिया है। शहरी संस्कृति ने राजनीतिक सोच–समझ की प्रवृत्तियों को भी परिवर्तित किया है। ग्रामीण संस्कृति में राजनीतिक–सामाजिक सम्बन्ध भावनाओं पर आधारित थे। वह अब परिवर्तित होकर भौतिकतावादी समझ में परिवर्तित हो गये है। शहरी संस्कृति पर आधारित समझना नयी राजनीतिक समझ को जन्म दिया। जिसने राज्य की चुनावी राजनीति और दलीय व्यवस्था में नये प्रतिरूप और स्वरूप का उद्‌भव हुआ है।

मूल्यांकन

हरियाणा की चुनावी राजनीति के परिवर्तित प्रतिरूप को समझना है तो इसके लिये आवश्यक है कि वर्तमानकालीन सामाजिक स्वरूप का व्यापक अध्ययन किया जाये। हरियाणा राज्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि राज्य का सामाजिक स्वरूप जिसमें जातीय विभेदन, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, खाप और डेरा व्यवस्था और ग्रामीण प्रभाव चारों निर्धारक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। जिससे राज्य में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के समर्थन आधार में कमी आई है और भाजपा वर्तमानकालीन समाजशास्त्रीय परिस्थितियों अनुकूल होने के कारण सहयोगी दल से सत्तारूढ़ दल की भूमिका में आ गयी है।

संदर्भ सूची

- Choudhary, Sunil K (2017). Democratic Transformation and Party System in Transition in Haryana. In Himanshu Roy, M.P. Singh and A.P.S Chouhan (2017). *State Politics in India*. New Delhi: Primus Books.
- Jodhka, Surinder S (2019). Haryana State Assembly Elections 2019: Puzzles and Patterns. *Economic & Political Weekly*. Vol- 54. No- 50.
- Jodhka, Surinder S (2018). Rural Change in Times of 'Distress. *Economic & Political Weekly.* Vol- 53. No-26.
- Kumar, Satendra (2016). The Time of Youth: Joblessness, Politics and Neo-religiosity in Uttar Pradesh. *Economic & Political Weekly*. Vol-51. No-53.
- Haryana Economic Survey Report 2023-24 (2024). *Department of Economics and Statistical Affairs, Haryana.* Government of Haryana.
- Census of India (2001 and 2011). *Office of the Registrar General and Census Commissioner, India*. Ministry of Home Affairs. Government of Haryana.

♦♦♦♦♦

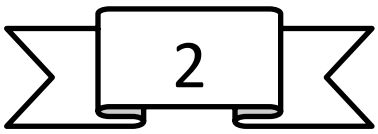

भारत में चुनाव शास्त्र विश्लेषणः हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर चुनाव अध्ययन

विकास यादव

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही भारत में लोकतंत्र की जड़े काफी मजबूत एवं गहरी है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु राजनीतिक दलों एवं मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय राजनीति के परिपेक्ष में अगर देखा जाए तो सुशासन के स्तंभ के रूप में राजनीतिक दल, राज्य एवं नागरिकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अतः चुनाव विज्ञान एवं चुनाव परिणाम के अंतरसंबंधों को समझना आवश्यक है, चुनाव विज्ञान को चुनाव विश्लेषण शास्त्र (Psephology) के रूप में समझा जा सकता है जिसमे की यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एक व्यवस्थित अध्ययन भारतीय चुनावों का योगेश अटल द्वारा 1967 में देखने को नजर आता है। चुनाव विज्ञान के माध्यम से यह समझ जा सकता है कि किस प्रकार चुनाव परिणाम परिणत होता नजर आता है।

अतः भारतीय राजनीति में आजादी के पश्चात् से ही विभिन्न संस्थाएं मतदाताओं के मध्य मत व्यवहार को जानने हेतु इस दृष्टिकोण की ओर अग्रसर नजर आई जिसमें वह चुनाव विश्लेषण शास्त्र के माध्यम से चुनावों का अध्ययन करने लगे। विभिन्न शोध गतिविधियों के माध्यम से चुनाव परिणाम का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया गया एवं मतदाताओं की वरीयता में आ रहे परिवर्तनों का अध्ययन भी इस प्रकार शुरू हुआ। इसी अनुरूप हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर के हालिया विधानसभा चुनावों की राजनीतिक को कैसे बदलते विन्यास में रखकर देखा जा सकता है एव विश्लेषण किया जा सकता हैं महत्वपूर्ण है।

जिसमें की सबसे पहले अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा की क्षेत्रीय राजनीति में एक नया आयाम एवं परिवर्तन नजर आया, 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव सभी चुनाव विश्लेषकों को चकित करता नजर आता है जिसमें की भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इन चुनाव में पराजय किया। राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा यह पूर्वानुमान लगाया गया कि हरियाणा की चुनावी राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व फिर से देखा जा सकता है। परंतु यह पूर्वानुमान जब चुनावी परिणाम में परिवर्तित हुआ तो धूमिल नजर आया

क्योंकि हरियाणा के मतदाताओं ने परिवर्तन को अपनाकर एक नई दिशा की ओर हरियाणा की राजनीति को अग्रसर किया। जिसमें की उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देकर विजयी बनाया अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट कर इन चुनाव में रह गई अन्य दलों द्वारा भी पांच सीटों को अर्जित किया गया। एक महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्य यहां यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मत प्रतिशत बहुत कम अंतर से देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 39.94 प्रतिशत मत प्राप्त किया गया वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 39.09ः मत प्राप्त किया गया अतः यह देखा जा सकता है कि दोनों दलों के मध्य मत प्रतिशत में काफी कम अंतर नजर आता है। हरियाणा के मतदाता 2024 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं रियल गेम चेंजर के रूप में उभरकर नजर आए। जिसमें की महिला मतदाता एवं युवा वर्ग हरियाणा की चुनावी राजनीति को अत्यधिक परिवर्तित करता नजर आता है। महिलाओं द्वारा विकास एवं अच्छे शासन के नाम पर वोट दिया गया वहीं युवा मतदाताओं द्वारा रोजगार उनकी प्राथमिकता नजर आती है। इसी अनुरूप यह देखा जा सकता है कि हरियाणा के मतदाताओं ने 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण रूप से भरोसा जताते हुए अपना समर्थन दिया।

एक अन्य राज्य जिसमें हरियाणा के साथ विधानसभा चुनाव को कराया गया वह जम्मू कश्मीर राज्य भी काफी चर्चित रहा। काफी लंबे समय के पश्चात् जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को कराया गया जिसमें की एक नया एवं नवीन परिवर्तन देखा गया। 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव ने भी एक नया आयाम स्थापित किया जिसमें कि अगर राजनीतिक दलों का परिणाम यानी उनके द्वारा किस प्रकार प्रदर्शन रहा इसका विश्लेषण करना अति आवश्यक है। 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठबंधन देखा गया। जिसमें की दोनों राजनीतिक दलों ने मिलकर 48 सीटे प्राप्त की और सरकार बनाने में सक्षम रही। जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस द्वारा 42 सीटे एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 6 सीटे प्राप्त की गई। वहीं दूसरी और भारतीय जनता पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपना अच्छा प्रदर्शन कर 29 सीटे प्राप्त की। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा यह दल मात्र तीन सीटे ही प्राप्त कर सका बाकी अन्य बची हुई सीटों पर क्षेत्रीय दल एवं निर्दयालों की पकड़ रही।

वहीं अगर मत प्रतिशत की बात की जाए तो 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस द्वारा 23.43 मत प्रतिशत प्राप्त किया गया। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

द्वारा 11.97 मत प्रतिशत प्राप्त किया गया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25.64 मत प्रतिशत प्राप्त किया गया एवं जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा 8.87 मत प्रतिशत प्राप्त किया गया। जम्मू कश्मीर में अगर मुद्दों की बात की जाए तो हमेशा से ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जम्मू कश्मीर की चुनावी राजनीति का मूल रूप से केंद्रीय हिस्सा रहे। जिसमें की लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जैसे कि आतंकवाद, अच्छा शासन, राजनीतिक स्थिरता, रोजगार, सुरक्षा इत्यादि पर बातें की गई। अतः 2024 का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव एक तरह से केंद्र बिंदु रहा।

अंततः विश्लेषण के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में चुनाव निरंतर समय पर होते हैं जिसमें की चुनावी प्रक्रिया एक उत्सव के रूप में मतदाताओं एव राजनीतिक दलों द्वारा मनायी जाती हैं। चुनावी प्रक्रिया द्वारा यह देखा जा सकता है कि चुनाव का मुख्य स्रोत जनता है। अतः लोकतांत्रिक देश में मुख्य शक्ति जनता में निहित होती है जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं निष्पक्ष चुनाव केंद्र बिंदु रहते हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो भारतीय राजनीति में नजर आता है वह यह है कि कैसे मतदाता अपने मत व्यवहार के माध्यम से क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय राजनीति में भी अंतर कर पता है। वह जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो उसके लिए क्षेत्रीय मुद्दे अहम हो जाते हैं उसी प्रकार जब राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो राष्ट्रीय मुद्दों को वह सर्वप्रिय रखता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में मतदाता जागरूक एवं सजग नजर आता है। जिसमें कि वह भारतीय राजनीति को न केवल समझता है बल्कि उसको मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए लोकतंत्र में अहम भूमिका भी निभाता हैं। उसी प्रकार राजनीतिक दलों के स्वभाव में भी बदलाव नजर आता है जिसमें की राजनीतिक दल निरंतर यह प्रयास करते हैं कि किस प्रकार वह मतदाताओं तक पहुंच सके एवं उनका समर्थन प्राप्त कर सकें। अतः लोकतंत्र में केंद्रीय स्तंभ के रूप में मतदाता, चुनावी प्रक्रिया एवं राजनीतिक दलों को देखा जा सकता है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देते हैं।

संदर्भ सूची

- Atal, Y. (2018). Chunaav Shashtra aur Rajneeti. (A.K. Dubey, Ed.) Pratimaan,11.
- Election Commission of India, 2024 Haryana Legislative Assembly Elections Statistical Report.
- Election Commission of India, 2024 Jammu & Kashmir Legislative Assembly Elections Statistical Report.

♦♦♦♦♦

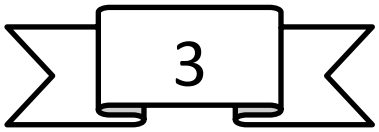

संख्याओं के परे सच्चाईः जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव का विश्लेषण

शशांक आचार्य

विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

एक दशक के लंबे अंतराल के बाद 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में आयोजित 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव इस क्षेत्र के राजनीतिक विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू–कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन के बाद आयोजित यह पहला चुनाव मात्र प्रक्रियात्मक महत्व से परे है। ये चुनाव राजनीतिक रूप से अस्थिर और संघर्ष–ग्रस्त क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की दृढ़ता को रेखांकित करते हैं। इन चुनावों ने न केवल राजनीतिक गठबंधनों और सामाजिक समीकरणों को पुनर्परिभाषित किया है, बल्कि लोकतंत्र, संघर्ष और चुनावी विज्ञान के आपसी संबंधों पर गहन शैक्षिक रुचि भी उत्पन्न की है।

चुनावी विज्ञान, जो सांख्यिकीय मॉडलिंग, सर्वेक्षण डेटा और एग्जिट पोल को समाहित करता है, परंपरागत रूप से मतदाता व्यवहार को समझने और चुनावी परिणामों का पूर्वानुमान लगाने में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। 1990 के दशक से, सर्वेक्षण अनुसंधान (Survey Research) चुनाव अध्ययन का पर्याय बन गया है, जो चुनावी नतीजों को आकार देने वाले कारकों में अनुभवजन्य अंतदृष्टि प्रदान करता है (Tawa, 2009). तथापि, इसकी मात्रात्मक दृष्टि प्राय प्रक्रियात्मक पहलुओं को मूल से अधिक प्राथमिकता देती है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक अंतर्धाराओं और उन सूक्ष्मताओं की अनदेखी होती है जो चुनावी परिणामों को गहराई से प्रभावित करती हैं।

2024 के जम्मू–कश्मीर चुनावों ने एक अनोखे सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में चुनाव विज्ञान की कार्यप्रणाली की मजबूती का परीक्षण किया, जो ध्रुवीकरण, ऐतिहासिक तनाव और सुरक्षा चुनौतियों से चिह्नित है। पूर्वानुमानों और परिणामों के मध्य विसंगतियों ने संघर्ष–ग्रस्त क्षेत्रों में पारंपरिक चुनावी उपकरणों की सीमाओं को उजागर किया। इसलिए, यह शोधपत्र तर्क देता है कि एग्जिट पोल और सांख्यिकीय मॉडल पर इस तरह की निर्भरता जम्मू–कश्मीर जैसे क्षेत्रों के जटिल सामाजिक–राजनीतिक ताने–बाने को अतिसरलीकृत करने का जोखिम उठाती है।

यह शोध–पत्र तर्क देता है कि जम्मू–कश्मीर चुनावों का जनादेश हमें चुनावी विज्ञान के प्रचलित ढांचों में निहित मूलभूत त्रुटियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करता है। केवल एग्जिट पोल और सांख्यिकीय मॉडलिंग पर संकीर्ण ध्यान केंद्रित करने से चुनावी विज्ञान महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विशेषताओं और व्यापक रूप से चुनाव प्रक्रिया के वस्तुनिष्ठ आयामों की अनदेखी करने का जोखिम उठाता है। जम्मू–कश्मीर का जनादेश प्रचलित निर्वाचन शास्त्रीय प्रथाओं (Psephological Practices) को चुनौती देता है, जहां विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्राय केवल मतदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो निश्चित रूप से चुनावी प्रक्रिया का चरम बिंदु है, लेकिन इसे चुनावी प्रक्रिया का एकमात्र रोचक पहलू मान लेना एक सीमित दृष्टिकोण है।

यह शोध–पत्र यह तर्क प्रस्तुत करता है कि 1990 के दशक से भारत में चुनावी परिणामों के पूर्वानुमान में चुनावी विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु इसकी मात्रात्मक पद्धतियों पर निर्भरता उल्लेखनीय सीमाएँ प्रस्तुत करती है। सांख्यिकीय त्रुटियाँ, परिस्थिति–जन्य सीमाएँ, और चुनावी परिणामों को मात्र संख्यात्मक पूर्वानुमानों तक सीमित कर देना, एक विविध और विषम समाज में सामाजिक और राजनीतिक कारकों की जटिल और गतिशील अंतःक्रियाओं को समझने में विफल रहता है। यह संकीर्ण दृष्टिकोण लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आकार देने वाल गहरे और संदर्भ–विशिष्ट प्रभावों की अनदेखी करने का जोखिम उठाता है।

इस संदर्भ में, 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव यह रेखांकित करते हैं कि वैकल्पिक विश्लेषणात्मक ढाँचों की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक, मानवशास्त्रीय, और राजनीतिक विश्लेषण पर आधारित दृष्टिकोणों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है जिन्हें व्यवहारवाद के प्रभुत्व के दौरान अक्सर उपेक्षित कर दिया गया। इन दृष्टिकोणों को मात्रात्मक तकनीकों के साथ संयोजित करने से चुनावी व्यवहार की अधिक विस्तृत और सटीक व्याख्या का मार्ग प्रशस्त होता है, जो मात्र संख्याओं से परे जाकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्रदान करती है।

रुझान बनाम परिणाम

जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावों का जनादेश संख्यात्मक अनुमानों और समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से किए गए विश्लेषण में एक उल्लेखनीय विरोधाभास प्रस्तुत करता है। 2014 के बाद पहली बार आयोजित इन चुनावों से व्यापक रूप से एक त्रिशंकु विधानसभा की उम्मीद की जा रही थी (Sen, 2024)। राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के अधिकांश एग्जिट पोल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस–कांग्रेस गठबंधन

के लिए 35–40 सीटें और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए 24–34 सीटों का पूर्वानुमान लगाया था, जबकि स्वतंत्र उम्मीदवारों और उभरते राजनीतिक दलों के लिए 23 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी, जिससे वे संभावित किंगमेकर की भूमिका में हो सकते थे (The Wire, 2024)।

अपितु, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से काफी भिन्न थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और उसके सहयोगियों ने 49 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया और सरकार बनाने में सक्षम हुए। एनसी ने अकेले 42 सीटों के साथ प्रमुख ताकत के रूप में उभरकर निर्णायक जीत दर्ज की, जबकि भाजपा ने 29 सीटें हासिल कीं। इसके विपरीत, कांग्रेस को अब तक के न्यूनतम प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, जिसमें वे केवल छह सीटें जीत सके, और एनसी के पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) मात्र तीन सीटों पर सिमट गई।

चुनावी विशेषज्ञों द्वारा किए गए संख्यात्मक विश्लेषण ने नए राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के प्रभाव को काफी बढ़ा–चढ़ाकर आंका था। अनुमानों में सुझाव दिया गया था कि इंजीनियर राशिद जैसे नेता, जो पिछली चुनावी उपलब्धियों पर निर्भर थे, महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। इसी तरह, अवामी इत्तेहाद पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और जम्मू–कश्मीर अपनी पार्टी जैसे उभरते दलों को भी उल्लेखनीय सफलता की उम्मीद थी। लेकिन ये दल उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और अधिकांश महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व हासिल करने में विफल रहे। इसके विपरीत, आम आदमी पार्टी (आप) ने डोडा सीट जीतकर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की, जबकि स्वतंत्र उम्मीदवार सामूहिक रूप से केवल सात सीटें जीत सके।

अनुमानों और वास्तविक परिणामों के बीच यह अंतर चुनावी विज्ञान की मात्रात्मक पद्धतियों (Quantitative) की सीमाओं को उजागर करता है। सांख्यिकीय मॉडलों ने मतदान प्रवृत्तियों का व्यापक अनुमान तो दिया, लेकिन वे मतदाताओं की जटिल निर्णय–प्रक्रिया और क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता को समझने में असमर्थ रहे। यह विरोधाभास इंगित करता है कि चुनावी व्यवहार की अधिक सटीक और व्यापक समझ के लिए सामाजिक–राजनीतिक और सांस्कृतिक जटिलताओं को ध्यान में रखने वाले गुणात्मक (Qualitative) दृष्टिकोणों को शामिल करने की आवश्यकता है।

वोट शेयर बनाम सीट शेयर

कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच जनसांख्यिकीय विभाजन से प्रभावित कई चुनाव विश्लेषकों ने 2024 के जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावों के अपने पूर्वानुमान और व्याख्याएँ क्षेत्रवाद और

सांप्रदायिक विभाजन के इर्द–गिर्द गढ़ी (The Hindu, 2024)। एग्जिट पोल काफी हद तक नतीजों से मेल खाते थे, जिसमें स्वायत्तता समर्थक लहर से प्रेरित मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में कांग्रेस–एनसी गठबंधन के लिए मजबूत प्रदर्शन और हिंदू बहुल जम्मू में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की गई थी। एनसी ने घाटी में 47 में से 35 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा ने जम्मू में 43 में से 29 सीटें जीतीं, जिसने स्पष्ट क्षेत्रीय विभाजन को रेखांकित किया।

परंतु सिक्के का दूसरा पहलू केवल मात्रात्मक विश्लेषण पर निर्भर रहने की भ्रांतियों को उजागर करता है। हालांकि, समग्र भविष्यवाणियां समग्र रुझानों के अनुरूप थीं लेकिन ऐसे व्याख्याओं ने वास्तव में महत्वपूर्ण बारीकियों को नजरअंदाज कर दिया। उदाहरण के लिए, भले ही भाजपा घाटी में सीटें नहीं जीत सकी, लेकिन कम उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के बावजूद इसका वोट शेयर 2014 में 2.5% से बढ़कर 2024 में 5.8% हो गया (The Indian Express, 2024)। यह वृद्धि मतदाता भावना में सूक्ष्म बदलावों को इंगित करती है, जिन्हें मात्रात्मक पूर्वानुमान पकड़ने में विफल रहे। यह तर्क दिया जा सकता है कि क्षेत्रीय एकरूपता पर अधिक जोर देने के कारण विश्लेषकों ने अंतःक्षेत्रीय भिन्नताओं और स्थानीय शिकायतों की अनदेखी की। यह जम्मू–कश्मीर जैसे राजनीतिक रूप से विविध क्षेत्र में मतदाता व्यवहार की जटिल और विकसित गतिशीलता को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करने में संख्यात्मक अनुमानों की सीमाओं को उजागर करता है। ये जटिलताएँ यह दर्शाती हैं कि मात्रात्मक विश्लेषण को पूरक करने और चुनावी विज्ञान के साथ–साथ विविध और खंडित राजनीतिक परिदृश्यों में चुनाव परिणामों की अधिक व्यापक समझ सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्याख्यात्मक ढाँचे आवश्यक हैं।

अनुमान बनाम परिणाम–परिसीमन और आरक्षण की सच्चाई

2022 में जम्मू–कश्मीर में किए गए परिसीमन अभ्यास, जिसमें जम्मू क्षेत्र में छह और कश्मीर में एक सीट जोड़ी गई, को व्यापक रूप से हिंदू–बहुल जम्मू क्षेत्र में भाजपा के प्रभाव को सुदृढ़ करने के प्रयास के रूप में देखा गया था। चुनावी विज्ञानियों का अनुमान था कि इस पुनर्विभाजन से भाजपा को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। सामान्य धारणा यह थी कि भाजपा, अपने मजबूत वैचारिक आधार और विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद नई परिसीमित क्षेत्रों में बड़ी बढ़त हासिल करेगी।

हालांकि, वास्तविक चुनाव परिणाम इन अनुमानों को चुनौती देते हैं (Ali, 2024)। भाजपा ने जम्मू में नई बनाई गई सात सीटों में से केवल चार पर जीत हासिल की, और कश्मीर में एक सीट गंवा

दी। यह परिणाम उस धारणा को जटिल बनाता है कि परिसीमन अभ्यास भाजपा के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए एक सीधी रणनीति थी। विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों और वास्तविक परिणामों के बीच यह विसंगति चुनाव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को रेखांकित करती है– मतदान व्यवहार को समझने में पहचान की राजनीति (Identity Politics) का अति सरलीकरण। परिणाम उन मान्यताओं को चुनौती देते हैं कि केवल जनसांख्यिकीय बदलाव ही चुनावी नतीजों को निर्धारित करेंगे, तथा चुनावी विश्लेषण में गहन क्षेत्रीय और पहचान–आधारित गतिशीलता पर विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

2024 जम्मू और कश्मीर विधानसभा में 90 में से 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षित की गईं, जो क्षेत्र के चुनावी ढांचे में पहली बार एसटी सीटों को शामिल करने का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने गुर्जर और बकरवाल समुदायों के साथ चार नई जनजातियों को एसटी सूची में शामिल किया। जबकि इन घटनाक्रमों का समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के प्रगतिशील प्रयासों के रूप में स्वागत किया जाना चाहिए था, चुनाव विशेषज्ञों ने इन्हें भाजपा के मतदाता आधार का विस्तार करने के उद्देश्य से सामाजिक इंजीनियरिंग के रूप में देखा, खासकर जब इन 9 में से 6 सीटें जम्मू में स्थित थीं, जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है (The Indian Express, 2024).

परिणाम उम्मीदों के विपरीत रहे, जहां भाजपा केवल दो एसटी सीटें जीत सकी और राजौरी और पुंछ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हार गई। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) और निर्दलीय उम्मीदवारों ने कई एसटी आरक्षित क्षेत्रों में अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन किया। यह परिणाम चुनावी पूर्वानुमानों की सीमाओं को उजागर करता है, जो आदिवासी समुदायों की राजनीतिक आकांक्षाओं की बारीकियों को पकड़ने में विफल रहे। यह जम्मू–कश्मीर में पहचान आधारित राजनीति के विश्लेषण के लिए मात्रात्मक सर्वेक्षणों की बजाय गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

संघर्ष क्षेत्रों में चुनाव विज्ञान की चुनौतियाँ

जैसा कि पिछले खंड से स्पष्ट है, जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सामाजिक व राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पारंपरिक चुनाव विज्ञान की सीमाओं को उजागर किया है। यह खंड उन कारकों की पड़ताल करता है जो चुनाव विज्ञान को ऐसे संदर्भों में चुनाव परिणामों की सटीक भविष्यवाणी करने से रोकते हैं।

स्थानीय और सामाजिक–राजनीतिक बारीकियों को कम आंकना

अधिकांश चुनाव विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि जम्मू और कश्मीर चुनाव के परिणाम अनुच्छेद 370, राज्य का दर्जा बहाली और सुरक्षा चिंताओं से जुड़े बहसों पर निर्भर करेंगे। लोकनीति–सीएसडीएस (CSDS) जैसे सर्वेक्षणों ने इन मुद्दों पर जोर दिया, जिसमें 60% से अधिक उत्तरदाताओं ने राज्य का दर्जा बहाल करने का समर्थन किया, 83ः ने कश्मीर घाटी में अनुच्छेद 370 को पुनः लागू करने का पक्ष लिया, जबकि जम्मू में यह आंकड़ा 42% था (जैम भ्पदकन, 2024)। हालांकि ये कारक व्यापक चुनावी परिणामों के साथ मेल खाते प्रतीत होते हैं, लकिन भाजपा के मजबूत प्रदर्शन ने इन मुद्दों पर अत्यधिक जोर को कम कर दिया। इसके अलावा, एक आलोचनात्मक विश्लेषण यह इंगित करता है कि पूर्व–चुनाव पूर्वानुमानों में स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज किया गया।

मतदाता की प्राथमिकताओं से राजनीतिक दल की कहानियों और जमीनी स्तर की चिंताओं के बीच अंतर का पता चला। जबकि पार्टियों ने संवैधानिक और राज्य के दर्जे की बहस पर जोर दिया, मतदाताओं का ध्यान आर्थिक चुनौतियों जैसे कि बेरोजगारी पर अधिक था, जो कि जम्मू–कश्मीर में 24.6% थी–जो राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर थी (Kashmir Reader, 2024)। भूमि स्वामित्व सुधारों जैसी नीतियों ने बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति दी और दरबार प्रथा को बंद कर दिया, जिससे छोटे व्यवसायों और स्थानीय भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, खासकर जम्मू में। ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष स्पष्ट था, जहां विकास के अधूरे वादों और कृषि घाटे के लिए देरी से मुआवजे ने मतदाताओं को अलग–थलग कर दिया। उधमपुर और कठुआ जैसे जिलों में, जो परंपरागत रूप से भाजपा के गढ़ रहे हैं, भूमि सुधारों से उत्पन्न सांस्कृतिक खतरों की धारणाओं के कारण पार्टी का वोट शेयर गिरा (The Hindu, 2024) ये परिस्थितियां चुनावी विश्लेषणों में स्थानीय और आर्थिक चिंताओं को शामिल करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं, जो चुनाव विज्ञान के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देती हैं।

जम्मू–कश्मीर के विधानसभा चुनावों पर 2020 से आयोजित जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनावों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिन्होंने राजनीतिक प्राथमिकताओं को स्थानीय मुद्दों, विशेष रूप से आजीविका, की ओर स्थानांतरित कर दिया। चुनाव विश्लेषक इस बदलाव को पकड़ने में असफल रहे। इन चुनावों ने व्यापक वैचारिक बहसों के बजाय स्थानीय शासन और आजीविका चिंताओं को प्राथमिकता देकर राजनीतिक प्राथमिकताओं को पुनर्परिभाषित किया। इसके अतिरिक्त, कश्मीर में युवाओं का असंतोष एक महत्वपूर्ण, लेकिन कम आंका गया, कारक बनकर उभरा। विशेष रूप से,

पहले से अलग–थलग पड़े समूहों, जैसे जमात–ए–इस्लामी और अन्य अलगाववादी आवाजों की भागीदारी ने पारंपरिक दलों के वोट बैंक में सेंध लगाई। इस बदलाव का परंपरागत दलों, विशेष रूप से पीडीपी, पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके वोट शेयर में 14% की तेज गिरावट दर्ज की गई, जो राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे बदलावों को दर्शाता है (Mint, 2024)।

सर्वेक्षण आधारित चुनाव विज्ञान की सीमाएँ– जम्मू और कश्मीर का मामला

एक सर्वेक्षण की अपनी सीमाएँ होती हैं, क्योंकि यह भारत में चुनावी व्यवहार और विकल्पों की विविध और सूक्ष्म जटिलताओं और अंतर्निहित धाराओं को पकड़ नहीं सकता है (Yadav, 2008)। जम्मू–कश्मीर एक प्रमुख भारतीय संघर्ष क्षेत्र है, जहाँ इसी तरह की गंभीर चिंताएँ हैं।

नमूनाकरण त्रुटि (Sampling Erros)

चुनाव विज्ञान अक्सर दूरदराज के गांवों और सीमावर्ती जिलों तक पहुँचने से जुड़ी रसद चुनौतियों और उच्च लागतों के कारण शहरी नमूना पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता है। इस पूर्वाग्रह ने संभवतः 2024 के जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावों के पूर्वानुमानों को प्रभावित किया। इस संदर्भ में सीजीएस समीक्षा (CGS Samiksha 2024*) सर्वेक्षणकर्ताओं ने ग्रामीण उत्तरदाताओं तक पहुँचने में कठिनाइयों को स्वीकार किया। CSDS चुनाव डेटा से भी यह सामने आता है कि शहरी, उच्च–मध्यम वर्ग, शिक्षित और उच्च–आय वर्गों की मतदान प्रवृत्तियाँ ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में काफी कम होती हैं (Rai, 2021)। इस प्रकार की गलत प्रतिनिधित्व चुनावी भविष्यवाणियों को विकृत करती है, और इन क्षेत्रों में अनुपलब्ध मतदाताओं की निर्णायक भूमिका को कम आंकती है। उदाहरण स्वरूप, श्रीनगर और बारामुला जैसे शहरी जिलों में क्रमशः 29.4% और 55.73% मतदान दरें दर्ज की गईं, जो चरण दो और तीन में सबसे कम थीं, जबकि सांबा, जिसमें 80% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या थी, ने अंतिम चरण में सबसे उच्च मतदान दर दर्ज की (PIB, 2024).

अप्रतिनिधि सैंपल प्रोफाइल (Unrepresentative Sample Profile)

विज्ञानियों का कहना है कि चुनावों में नमूना सर्वेक्षण तब विफल हो सकते हैं जब वे महत्वपूर्ण जाति और समुदाय समूहों को नजरअंदाज करते हैं। मीडिया के सर्वेक्षण आमतौर पर कोटा सैंपलिंग पर निर्भर करते हैं, जिसमें लिंग, शिक्षा, जाति और आयु के आधार पर उत्तरदाता की संख्या तय की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे नमूने बनते हैं जो मतदाता समूह का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। 2024 के जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावों में, महत्वपूर्ण मतदाता समूह, जैसे कि

पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी, वाल्मीकी समाज और गोरखा समुदाय, जो पहली बार मतदान कर रहे थे—संभावना है कि वे सर्वेक्षणों में कम प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, हजारों कश्मीरी पंडितों की भागीदारी, विशेष रूप से वे जो दिल्ली में स्थापित मतदान केंद्रों में मतदान कर रहे थे, शायद क्षेत्रीय सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा पूरी तरह कैप्चर नहीं की जा सकी। इन अनदेखे समूहों ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया होगा, जो यह दर्शाता है कि चुनाव विज्ञान की भविष्यवाणी क्षमता में एक प्रमुख सीमा है जब महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को सर्वेक्षण विधियों में शामिल नहीं किया जाता। एक अन्य कम प्रतिनिधित्व वाले समूह के रूप में महिलाएं थीं, जिनके बारे में सीजीएस (CGS*) सर्वेक्षणकर्ताओं ने बताया कि कई महिला उत्तरदाता भाग लेने में संकोच कर रही थीं, और जो भाग लेती थीं, वे अक्सर अपनी प्रतिक्रियाओं को पुरुष साथियों के अनुरूप व्यक्त करती थीं। इसके बावजूद, महिलाओं की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जैसा कि चुनाव आयोग के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि पहले चरण में छह निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाता दर पुरुषों से अधिक थी, और दूसरे चरण में यह प्रवृत्ति 11 निर्वाचन क्षेत्रों तक फैल गई।

अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य (Volatile Politcal Landsacpe)

कश्मीर जैसे संघर्ष क्षेत्रों में मतदाता अस्थिर हैं, मतदान के इरादे अक्सर चुनाव के दिन के करीब बदल जाते हैं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण गलत होते हैं क्योंकि वे अस्थिर मतदाताओं के व्यवहार को पकड़ने में विफल रहते हैं। 2024 के जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावों में, उत्तरदाताओं ने एक दशक के केंद्रीय शासन के कारण भाजपा के लिए समर्थन व्यक्त किया हो सकता है, लेकिन वे चुनाव के दिन अलग तरह से मतदान कर सकते थे। यह बदलाव व्यापक निगरानी वातावरण से प्रभावित है, जहां प्रतिशोध के डर से मतदाता सर्वेक्षण के दौरान अपनी वास्तविक प्राथमिकताओं को छिपाते हैं। ये गतिशीलता राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की सीमाओं को उजागर करती है।

2024 के जम्मू और कश्मीर चुनावों ने पारंपरिक चुनावी विज्ञान में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया, विशेष रूप से संघर्ष क्षेत्र में जहाँ स्थानीय जटिलताएँ मतदाता व्यवहार को आकार देती हैं। एक्जिट पोल में असत्यताएँ और परिवर्तनशील मतदान इरादों को ध्यान में न रखने से चुनावी भविष्यवाणियों में बदलाव की आवश्यकता उजागर होती है। प्रासंगिक बने रहने के लिए, चुनावी विज्ञान को क्षेत्र–विशेष गुणात्मक जानकारी को शामिल करना चाहिए और डेटा संग्रह की चुनौतियों का समाधान करना चाहिए। ये चुनाव यह सिद्ध करते हैं कि एक मिश्रित विधि दृष्टिकोण, जो

गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीकों को जोड़ती है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर को बेहतर समझने के लिए आवश्यक है।

टिप्पणियाँ

'सीजीएस समीक्षा 2024: जम्मू और कश्मीर, सीजीएस द्वारा आयोजित व्यापक चुनाव सर्वेक्षण श्रृंखला का भाग है, जो कि चुनावी अध्ययन के क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्रीय शोध संस्थान है। यह सर्वेक्षण, जम्मू और कश्मीर के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है, मतदान पैटर्न और चुनावी रुझानों का आकलन करने के लिए चरणों में आयोजित किया गया था। लेखक सर्वेक्षण करने वाली टीम का भाग थे।

संदर्भ सूची

- Ali, J. (2024). Delimitation may have failed to boost BJP in key Jammu constituencies, analysis shows. The Wire
- Election Commission of India. (2024). Partywise results - Jammu and Kashmir Assembly Elections 2024. ECI.
- Indian Express. (2024). First battle for Jammu's ST seats: Pahari-Gujjar divide, BJP's India role, and a reversal. The Indian Express
- Kashmir Reader. (2024). Unemployment crisis in Jammu and Kashmir: A growing concern. Kashmir Reader
- LiveMint. (2024). Jammu and Kashmir election results 2024. Live Mint.
- Press Information Bureau. (2024). Press release on Jammu and Kashmir Assembly elections.
- Rai, P. (2021). Psephological fallacies of public opinion polling. Economic and Political Weekly 58
- Sen, R. (2024). J&K and Haryana Assembly Elections: An analysis of the verdicts. Institute of South Asian Studies, National University of Singapore.
- Tawa, S. (2009). Studying elections in India: Scientific and political debates. South Asia Multidisciplinary Academic Journal, 3
- The Hindu. (2024). Methodology of the Lok Niti-CSDS post-poll survey in Jammu and Kashmir. The Hindu.
- The Hindu. (2024). Regional patterns of voting show divide between Jammu, Kashmir. The Hindu.
- The Wire. (2024). J&K elections: A watershed moment in the region's political history. The Wire.
- Yadav, Y. (2008). "Whither Survey Research? Reflections on the State of Survey Research on Politics in Most of the World," Malcolm Adiseshiah Memorial Lecture, Chennai.

♦♦♦♦♦

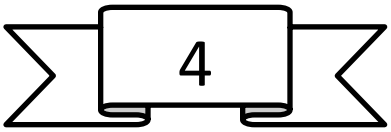

हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर में चुनाव विज्ञान व चुनाव परिणामों का तुलनात्मक विश्लेषण

नीलम

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

चुनाव विज्ञान व वास्तविक विश्व के चुनाव परिणामों का प्रतिच्छेदन सामान्यतः आकर्षक विसंगतियों और अंतदृष्टि को सामने लाता है। हरियाणा व जम्मू और कश्मीर जैसे भारतीय राज्यों में, जहाँ क्षेत्रीय राजनीति मतदाता व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित करती है, चुनाव विज्ञान पर आधारित भविष्यवाणियों और अंतिम परिणामों के मध्य का अंतर चौंकाने वाला हो सकता है। जबकि चुनाव विज्ञान, जो पूर्वानुमान मॉडल, मतदान डेटा और जनसांख्यिकीय विश्लेषण पर निर्भर करता है, चुनाव परिणामों को समझने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, वास्तविक परिणाम कभी–कभी अपेक्षाओं को धता बताते हैं। यह लेख हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव विज्ञान और वास्तविक चुनाव परिणामों के तुलनात्मक विश्लेषण की पड़ताल करता है, जिसमें यह जाँच की जाती है कि कैसे पूर्वानुमान और वास्तविक जीवन के परिणाम अलग–अलग होते हैं।

चुनाव विज्ञानः भविष्यवाणी

चुनाव विज्ञान में चुनाव के परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए सांख्यिकीय मॉडल और जनसांख्यिकीय डेटा का अध्ययन सम्मिलित है। यह मतदाता व्यवहार व संभावित विजेताओं के बारे में पूर्वानुमान देने के लिए जनमत सर्वेक्षण, बड़े डेटा विश्लेषण करता है। विशेषज्ञ ऐतिहासिक डेटा, सोशल मीडिया ट्रेंड, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, आर्थिक स्थिति और क्षेत्रीय मुद्दों का विश्लेषण करके यह पता लगाते हैं कि चुनाव के परिणाम कैसे दिख सकते हैं।

हरियाणा और जम्मू–कश्मीर दोनों के लिए, चुनाव विज्ञान परिणामों की भविष्यवाणी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जाति, धर्म और क्षेत्रीय संबद्धता जैसे जनसांख्यिकीय कारक मतदान

व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से आकार देते हैं, और चुनाव विज्ञान इन जटिल पैमाने को मापने का प्रयास करता है। हरियाणा में, जहाँ कृषि संकट, जातिगत राजनीति और शहरीकरण महत्वपूर्ण कारक हैं, वैज्ञानिक ग्रामीण बनाम शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के प्रभुत्व की भविष्यवाणी करने के लिए मॉडल बना सकते हैं। इसी प्रकार, जम्मू व कश्मीर का अनूठा राजनीतिक परिदृश्य– क्षेत्रीय स्वायत्तता, जम्मू और लद्दाख की स्थिति और सुरक्षा चिंताओं जैसे कारकों से आकार लेता है – चुनाव विज्ञान के लिए परिणामों की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए उपकरणों के एक अलग सेट की आवश्यकता होती है।

विशेष रूप से, पोलस्टर डेटा एकत्र करने के लिए एग्जिट पोलिंग और चुनाव–पूर्व सर्वेक्षण जैसे तरीकों का उपयोग करते हैं। जबकि मतदान पद्धतियाँ अधिक परिष्कृत हो गई हैं, इन भविष्यवाणियों की सटीकता वाद–विवाद का विषय बनी हुई है।

चुनाव विज्ञान की भविष्यवाणियों की विफलताएँ

अपनी कठोरता के बावजूद, चुनाव विज्ञान परिपूर्णता से बहुत दूर है। यह प्रायरू चुनाव के परिणामों का सटीक अनुमान लगाने में विफल रहता है, विशेषकर हरियाणा और जम्मू–कश्मीर जैसे राज्यों में, जहां अप्रत्याशित चर भूमिका निभाते हैं। चुनाव वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ो चुनौतियों में से एक मतदाता व्यवहार की अप्रत्याशितता है। मानवीय भावनाएं, स्थानीय भावनाएं और अप्रत्याशित घटनाएं अक्सर वैज्ञानिक पूर्वानुमानों को बाधित करती हैं। उदाहरण के लिए, हरियाणा में, 2019 के चुनावों में अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिले। विश्लेषकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मध्य कांटे की टक्कर की भविष्यवाणी की थी। तथापि, अंतिम परिणामों में भाजपा की निर्णायक जीत दिखाई गई, जिसका मुख्य कारण शहरी मतदाताओं के लिए इसकी अपील और ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में इसका सफल अभियान था, जहां कृषि मुद्दे प्रभावी थे। स्थानीय मुद्दां पर जीत प्राप्त करने और विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करने की भाजपा की क्षमता ने अंततः पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ दिया, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी के प्रभाव को कम करके आंका। इसी प्रकार, जम्मू और कश्मीर में, राजनीतिक माहौल की अप्रत्याशितता अक्सर पूर्वानुमानों को भ्रमित करती है। 2019 के राज्य चुनाव अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से प्रभावित हुए, जिसने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया। चुनाव वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाने में कठिनाई हुई कि केंद्र सरकार के विवादास्पद कदम के बाद राजनीतिक माहौल कैसे बदलेगा। जबकि कुछ ने क्षेत्रीय दलों से प्रतिक्रिया की आशंका जताई, दूसरों ने तर्क दिया कि

इससे राष्ट्रीय स्तर पर अधिक एकीकरण हो सकता है। वास्तव में, इसके बाद राजनीतिक पुनर्संयोजन की ओर बदलाव देखा गया, जिसमें भाजपा जम्मू में मजबूत होकर उभरी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने कश्मीर में अपना प्रभाव बनाए रखा। ये परिणाम क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण और राष्ट्रीय भावना के जटिल मिश्रण को दर्शाते हैं– ऐसे कारक जिन्हें मापना मुश्किल है।

चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले वास्तविक–विश्व कारक

जबकि चुनाव विज्ञान मूल्यवान अंतदृष्टि प्रदान करता है, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में चुनावों के वास्तविक परिणाम प्रदर्शित करते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य कितना जटिल और बहुआयामी हो सकता है। हरियाणा में, स्थानीय उम्मीदवारों का प्रभाव प्रायः पार्टी के पूर्वानुमानों पर भारी पड़ता है। व्यक्तिगत करिश्मा, समुदायों के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव और मजबूत जमीनी स्तर पर प्रचार मतदाता के निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, जल की कमी, किसानों का विरोध प्रदर्शन, तथा कृषि संकट से निपटन के लिए राज्य सरकार के तरीके जैसे मुद्दे मतदान व्यवहार को इस तरह से आकार देते हैं, जिसका वैज्ञानिक पूर्वानुमान हमेशा नहीं लगाया जा सकता।

जम्मू और कश्मीर में, क्षेत्र की अस्थिर सुरक्षा स्थिति मतदाता भावना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगातार आतंकवादी हमले, राजनीतिक अशांति और सैन्य उपस्थिति ने ऐसा माहौल बनाया है, जहाँ भविष्य के बारे में जनता का डर और अनिश्चितता चुनावी निर्णयों में भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल भी इन आशंकाओं का लाभ उठाते हैं, या तो विद्रोहियों पर नकेल कसने का वादा करते हैं या स्थानीय समुदायों के अधिकारों की वकालत करते हैं। ये तत्व चुनाव विज्ञान के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल बनाते हैं कि मतदाता उन अभियानों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे जो स्वायत्तता या संघवाद की आकांक्षाओं के साथ सुरक्षा चिंताओं को जोड़ते हैं।

मतदान डेटा और चुनाव परिणामों में विसंगतियां

मतदान डेटा, जो चुनाव विज्ञान के लिए केंद्रीय है, पूर्वानुमानों और वास्तविक परिणामों के बीच विसंगति का एक प्रमुख स्रोत भी हो सकता है। पोल अक्सर कुछ प्रमुख मीट्रिक, जैसे कि पार्टी की वफादारी और उम्मीदवार की स्वीकृति रेटिंग पर ध्यान केंद्रित करके मतदाता व्यवहार को सरल बना देते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया की स्थितियों में मतदाताओं को प्रभावित करने वाले प्रभावों के पूरे स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं।

हरियाणा के 2019 के चुनावों में, एग्जिट पोल ने शुरू में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर का सुझाव दिया था। हालांकि, जैसे–जैसे नतीजे सामने आए, यह स्पष्ट हो गया कि चुनावों में भाजपा की अपील को कम करके आंका गया था। डेटा भाजपा के ग्रामीण समर्थन आधार की ताकत को पूरी तरह से दर्शाने में विफल रहा, क्योंकि कई ग्रामीण मतदाताओं ने या तो मतदान नहीं किया था या फिर उन्होंने मतदान करने वालों को अपने मतदान के इरादे का खुलासा नहीं किया था। इस विसंगति के कारण कांग्रेस की संभावनाओं का अधिक आकलन किया गया और वास्तविक चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को कम करके आंका गया। इसी तरह, जम्मू और कश्मीर में, क्षेत्र के अनूठे राजनीतिक माहौल के कारण मतदान के आंकड़ों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक अशांति और सुरक्षा चिंताओं से चिह्नित माहाल में, कई मतदाता अपनी पसंद को मतदान करने वालों के साथ साझा करने में अनिच्छुक हो सकते हैं, जिससे अविश्वसनीय डेटा सामने आते हैं। जब अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद चुनाव हुए, तो मतदान के आंकड़ों में केंद्र सरकार और कश्मीर के विशेष दर्जे के प्रति उसके दृष्टिकोण के प्रति मतदाताओं के रवैये में बदलाव को शामिल नहीं किया गया।

निष्कष अधिक गतिशील दृष्टिकोण की आवश्यकता

हरियाणा और जम्मू–कश्मीर में चुनाव विज्ञान और वास्तविक विश्व के चुनाव परिणामों के मध्य तुलनात्मक विश्लेषण वर्तमान पूर्वानुमान मॉडल की सीमाओं को प्रकट करता है। जबकि चुनाव विज्ञान मतदान व्यवहार और चुनावी रुझानों में मूल्यवान अंतदृष्टि प्रदान करता है, यह मानव व्यवहार, राजनीतिक भावना और क्षेत्रीय मुद्दों के गतिशील, अप्रत्याशित तत्वों को पूरी तरह से पकड़ नहीं सकता है। स्थानीय उम्मीदवारों की लोकप्रियता, राजनीतिक पुनर्संरेखण, सुरक्षा चिंताएँ और अंतिम समय की अभियान रणनीतियाँ जैसे कारक अक्सर वैज्ञानिक मॉडल की भविष्यवाणियों को धता बताते हैं।

सटीकता में सुधार करने के लिए, चुनाव विज्ञान को अधिक लचीला, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो मतदाता निर्णयों को आकार देने वाले कारकों के जटिल परस्पर क्रिया को ध्यान में रखता हो। स्थानीय मुद्दों, क्षेत्रीय गतिशीलता और मनोवैज्ञानिक कारकों की गहरी समझ क साथ पारंपरिक जनसांख्यिकीय विश्लेषण को जोड़ने से अधिक सटीक भविष्यवाणियाँ हो सकती हैं।

अंततः, जबकि चुनाव विज्ञान विकसित हो रहा है और मतदाता व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है, हरियाणा और जम्मू–कश्मीर में पूर्वानुमानों और वास्तविक

परिणामों के मध्य का अंतर मानव निर्णय लेने में निहित जटिलताओं की याद दिलाता है। जैसे–जैसे राजनीतिक वैज्ञानिक अपने तरीकों को परिष्कृत करते जा रहे हैं, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चुनावी परिणाम केवल आंकड़ों का उत्पाद नहीं हैं– वे निरंतर बदलते राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिबिंब भी हैं।

♦♦♦♦♦

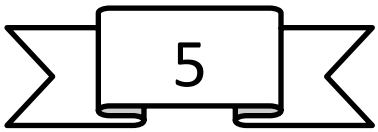

हरियाणा और जम्मू–कश्मीर चुनाव विश्लेषणः चुनाव विज्ञान का एक अध्ययन

कमल कुमार हुड्डा

विधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भूमिका

हरियाणा और जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावों का विश्लेषण करते समय लोगों के मन में यह प्रशन अवश्य आता है कि एग्जिट पोल चुनाव नतीजों से मेल क्यों नहीं खाते अथवा विभिन्न पोलस्टर्स द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ चुनाव नतीजों से मेल क्यों नहीं खातीं? हरियाणा एक ऐसा राज्य है, जहां कई सर्वेक्षण संगठनों द्वारा यह दावा किया गया था कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और भाजपा सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन चुनाव परिणाम पूरी तरह से विपरीत रहे और भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। जम्मू और कश्मीर, एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद 10 साल बाद चुनाव हुए। जम्मू और कश्मीर में एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम मिश्रित सटीकता के साथ आए। इससे चुनाव विज्ञान बनाम चुनाव परिणाम का अध्ययन करने तथा चुनावों की भविष्यवाणियों, कार्यप्रणाली, अनुमानों और धारणाओं का विश्लेषण करने की जिज्ञासा विकसित हा सकती है।

भारत में चुनाव विज्ञान का अध्ययन

चुनाव विज्ञान, राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जो चुनाव प्रक्रिया या चुनाव कैसे संचालित और लड़े जाते हैं, इसका अध्ययन करती है। यह चुनाव अध्ययन पर अपनी जानकारी को सुनिश्चित करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों का उपयोग करता है। इसमें चुनाव कानून, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, मतदान कार्यप्रणाली, आदि का अध्ययन शामिल है। सेफोलॉजी, चुनाव विज्ञान के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है जो चुनाव अध्ययन और परिणामों से निकटता से जुड़ा हुआ है। मूल रूप से, सेफोलॉजी को चुनावों और मतदान कार्यप्रणाली के वैज्ञानिक और सांख्यिकीय अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। चुनाव का अध्ययन करने वाले को चुनाव

विश्लेषक (Psephologist) के रूप में जाना जाता है और कुछ प्रसिद्ध भारतीय चुनाव विश्लेषकों में रजनी कोठारी, योगेन्द्र यादव, सुहास पलशिकर, राजीव कुमार आदि शामिल हैं। भारत में चुनाव अनुसंधान में सर्वेक्षण, फोकस समूह विश्लेषण, जनमत सर्वेक्षण और एग्जिट पोल के माध्यम से लगे हुए कई मतदान संगठन हैं। उदाहरण के लिए, सीवोटर (Cvoter), सीएसडीएस (सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज), लोकनीति, कल्याण चंद्रा, एक्सिस माई इंडिया और कई अन्य। मतदाता व्यवहार का अध्ययन करने और मतदान के इरादों को समझने के लिए चुनाव विश्लेषक जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, आय, व्यावसायिक पृष्ठभूमि आदि जैसे विभिन्न चुनावी पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। 1950, के दशक में जनमत और भारतीय मतदाताओं का अध्ययन करने के लिए IIPO यानी श्इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियनश की स्थापना की गई थी, लेकिन 1963, में रजनी कोठारी ने CSDS (सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज) की स्थापना की, जहाँ चुनाव विज्ञान को एक अकादमिक अनुशासन के रूप में पढ़ाया जाता हैं। हाल के दिनों में, NDTV और ABP न्यूज जैसे मीडिया भी चुनाव अध्ययन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जिससे चुनाव विज्ञान संबंधी अध्ययनों का दायरा बढ़ रहा है।

हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर चुनावः चुनावी भ्रांतियों एवं त्रुटियों का बोध

हरियाणा और जम्मू–कश्मीर में 2024 में होने वाले चुनावों से पहले लगभग सभी पोलिंग संगठनों ने अपने सर्वेक्षणों और धारणाओं के आधार पर एक जैसी भविष्यवाणी की, जिसमें हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत बढ़त दिखाई गई और जम्मू–कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव में आगे चल रहे थे। हालांकि जम्मू–कश्मीर के चुनाव परिणाम किसी तरह से चुनाव आयोग के चुनाव अनुमानों से मेल खा रहे थे, लेकिन हरियाणा में चुनाव की भविष्यवाणी बुरी तरह से गलत रही और चुनाव परिणामों के बिल्कुल विपरीत थी। पोलिंग संगठन, कांग्रेस की मजबूत जीत और भाजपा की हार की वकालत कर रहे थे, लेकिन भाजपा को 90 में से 48 सीटें मिलीं और कांग्रेस को 37 सीटें मिलीं।

2019, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला, जहां पोलिंग एजेंसियों ने दावा किया कि भाजपा को 90 में से 65 से 70 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस 11–17 सीटों के बीच रहेगी। 2019, हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल बुरी तरह विफल रहे और चुनावी अनुमानों पर पानी फिर गया, जहां भाजपा 40 सीटों और कांग्रेस 31 सीटों पर सिमट गई।

मतदान संगठनों के पूर्वानुमान विफल होने और चुनाव परिणामों के गलत होने के पीछे निम्नलिखित कारण हैं–

भारत एक अत्यधिक विविधतापूर्ण राष्ट्र है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक–जातीय–धार्मिक–भाषाई विविधताएं हैं, इसलिए मतदान संगठनों के लिए मतदान व्यवहार को मापना और मतदाताओं के मतदान के इरादे को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतदाताओं की विविधता किसी भी तरह के राजनीतिक पद्धति और मतदाताओं की राजनीतिक निष्ठा को समझने में बाधा डालती है और एक ही मतदाता कई पहचान जैसे धार्मिक, जाति, समुदाय, वर्ग, व्यावसायिक समूह आदि रख सकता है, जिससे उनके राजनीतिक विकल्पों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है।

भारत प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली का प्रमुख उदाहरण है, जहाँ दो से अधिक राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव तब दिलचस्प हो जाते हैं जब दो या दो से अधिक प्रमुख राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हों, प्रतिस्पर्धा कर रहे हों और प्रचार कर रहे हों। लेकिन, इससे गलत पूर्वानुमान का जोखिम बढ़ जाता है क्योंकि उत्तरदाता मिश्रित उत्तर देते हैं। हालाँकि, हरियाणा में चुनावी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच रही, लेकिन INLD (भारतीय राष्ट्रीय लोक दल) और JJP (जननायक जनता पार्टी) भी चुनावों को प्रभावित कर रहे थ। जम्मू–कश्मीर को ध्यान में रखते हुए, चुनावी लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC), भाजपा और कांग्रेस के बीच रही, लेकिन PDP (पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी), CPI (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी), AAP (आम आदमी पार्टी) और अन्य पार्टियाँ भी मतदाताओं की पसंद को प्रभावित कर रही थीं।

चुनावी शोध और मतदान संगठन अपने सर्वेक्षणों में सटीकता की भविष्यवाणी करने में विफल होने का एक प्रमुख कारण सीमित जनसांख्यिकीय कवरेज या पहुंच है। आम तौर पर, डेटा संग्रह शहरी क्षेत्रों या उच्च वर्ग या जाति से किया जाता है, इसके अलावा डेटा एक विशिष्ट लिंग, पुरुष से भी एकत्र किया जाता है। हर जाति, वर्ग और लिंग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होने के कारण, डेटा पक्षपाती होता है एवं गलत परिणाम देता है। यह त्रुटि हरियाणा चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है जहाँ मीडिया सर्वेक्षण, मतदान संगठन सर्वेक्षण, सोशल–मीडिया, सभी कांग्रेस की चुनावी सफलता की वकालत कर रहे थे लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत रहे।

मतदाताओं की चुनावी प्राथमिकताएँ चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी में अशुद्धि का एक और कारण हैं। भारतीय मतदाता फ्लोटिंग वोटर (सिवंजपदह अवजमते) बन गए हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे मतदाता जिनके पास मतदान की कोई निश्चित पद्धति नहीं है, वे विचारधारा या निष्ठा क आधार

पर मतदान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे चुनाव के दिन अपना वोट तय करते हैं। जैसा कि प्रोफेसर सुनील कुमार चौधरी ने बिल्कुल सही कहा है कि आज के मतदाता फ्लोटिंग वोटर (Floating voters) और टैक्टिकल वोटर (Tactical voters) से हटकर साइलेंट वोटर (Silent voters) बन गए हैं, जो अभिव्यक्तिपूर्ण हुए बिना निर्णायक हैं और यह प्रवृत्ति वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है और लोकतांत्रिक चुनावों को प्रभावित कर रही है।

चुनाव विश्लेषक और मतदान संगठन भारतीय राजनीति में हाल के रुझानों को समझने में विफल रहे या फिर उन्होंने उन्हें कमतर आंका। उदाहरण के लिए 2014, के बाद भारतीय राजनीति में दक्षिणपंथी रुझान, जिसे मोदी लहर भी कहा जा सकता है, 2014 के बाद भारतीय राजनीति में भाजपा के वोट शेयर और सीट शेयर में भारी वृद्धि देखी गई, जिसने मतदाताओं की चुनावी प्राथमिकताओं को प्रभावित किया। हरियाणा में जाट राजनीति से गैर–जाट राजनीति की ओर बदलाव हुआ, भाजपा ने ओ.बी.सी. (OBC) वर्ग को अपने पक्ष में किया, जो हरियाणा की आबादी का 35% है और पिछड़ी जाति की राजनीति का उदय हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी ने भी मतदाताओं की पसंद को प्रभावित किया, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जम्मू–कश्मीर में खासकर अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद मतदाताओं का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है।

चुनावी भ्रांतियों एवं त्रुटियों में सुधार

चुनाव संबंधी भ्रांतियों को समायोजित या ठीक करने के लिए विभिन्न तरीके हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है –

- मतदाताओं का उचित प्रतिनिधित्व–नमूना आकार (sample size) लगभग हर जनसांख्यिकीय स्थान को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए और इसमें सभी लिंग, जाति, वर्ग और समुदाय शामिल होने चाहिए। इससे विषम समाज के प्रबंधन में भी मदद मिलेगी।
- नमूनाकरण विधि में सुधार करें– सबसे सटीक नमूनाकरण विधियों में से एक सरल यादृच्छिक नमूनाकरण माना जाता है, जहां सभी के पास चुने जाने की समान संभावना होती है, लेकिन साथ ही, नमूनाकरण विधि को जनसांख्यिकीय स्थान की स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार चना जाना चाहिए।

- डेटा संग्रहण और डेटा विश्लेषण – सर्वेक्षणकर्ता का मुख्य ध्यान आसान, उत्तर देने योग्य और गैर–विवादास्पद प्रश्न पूछने पर होना चाहिए, जिन्हें डेटा में परिवर्तित किया जा सके और व्याख्या करने के लिए आगे उनका विश्लेषण किया जा सके।
- डेटा में हेरफेर से बचना– पक्षपातपूर्ण परिणाम दिखाने के लिए डेटा में हेरफेर से पूरी तरह बचना चाहिए क्योंकि यह अनैतिक और गैर–पेशेवर कार्य है।
- चुनाव विज्ञान को समकालीन नीति अनुसंधान से जोड़ना – चुनावों में हालिया रुझान जैसे मुफ्त की राजनीति, धार्मिक राजनीति, कल्याणकारी योजनाएं, शासन का संचालन का विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि मतदाता व्यवहार, मतदान पद्धति और मतदान के इरादों के बारे में बेहतर समझ प्राप्त हो सके।
- पारदर्शिता और जवाबदेही– सभी प्लेटफॉर्म जो चुनाव सर्वेक्षण कर रहे हैं और एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं, उन्हें चुनाव सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में पारदर्शी होना चाहिए और चुनावों की गलत भविष्यवाणियों के लिए जवाबदेह होना चाहिए।

मूल्यांकन

लोगों की धारणाओं के साथ मतदान संगठनों द्वारा भविष्यवाणियां की जाती हैं और भविष्यवाणियों के साथ, मतदान व्यवहार, मतदान पद्धति और मतदान के इरादे को इन संगठनों द्वारा समझा जाता है। चुनाव, सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए त्योहार होते हैं और जनता, मतदाताआं की चुनावी प्राथमिकताओं और विकल्पों को समझने के लिए उन पर अत्यधिक भरोसा करती है। लेकिन, समस्या तब उत्पन्न होती है जब चुनाव की भविष्यवाणी, चुनाव अनुमानों या चुनाव परिणामों से मेल नहीं खाती। 2024, का हरियाणा विधानसभा चुनाव इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां चुनाव भविष्यवाणी और चुनाव परिणाम विपरीत हैं और एग्जिट पोल में हारने वाली पार्टी राज्य में पूर्ण बहुमत से जीत जाती है। चुनावी भ्रांतियां एवं गलत चुनाव भविष्यवाणी, एग्जिट पोल और उनकी सफलता पर लोगों का भरोसा तोड़ती हैं। इन भ्रांतियों के कइ कारण हैं जैसे विषम समाज, उच्च विविधता, अस्थिर और मूक मतदाता, डेटा हेरफेर आदि, लेकिन लोगों का विश्वास और भरोसा फिर से हासिल करने के लिए इन पर जाँच और नियंत्रण किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

- Choudhary, Sunil k. (2024). *India @ 75 A changing Electoral Democracy.* Aakar Books, p-24.
- Congress To Get 42% Votes, BJP 37%: Here's What CSDS-Lokniti's Pollster Predicted for Haryana Elections. (2024, October 7), *ABP News.* https://news.abplive.com/elections/haryana-assembly-elections-congress-bjp-result-voter-percentage-csds-lokniti-1722729
- Kumar, Sanjay, Rai, Praveen and Gupta, Pranav (2016): 'Do surveys influence results?', *Seminar*, 684, August 2016.
- Rai, Parveen. (2021, August 06). Psephological Advancements and Pitfalls of Political Opinion Polls in India. *Open Political Science.* Pp- 258-274.
- Rai, Parveen. (2021). Psephological Fallacies of Public Opinion Polling. *Economic and Political weekly.* vol LVI no 28, pp- 51-57.
- Sanyal, Anindita. (2019, October 22). Haryana Election 2019: Sweep For BJP's Manohar Lal Khattar in Haryana, Exit Polls Show. *NDTV Elections.* https://www.ndtv.com/india-news/haryana-poll-of-polls-election-in-haryana-2019-sweep-for-manohar-lal-khattar-ml-khattar-exit-poll-2120433
- Sharma, Sheenu. (2024, October 07). Haryana exit poll 2024: Congress set to make comeback with 59 seats after a decade, setback for BJP, *India TV. https://www.indiatvnews.com/haryana/haryana-exit-polls-results-2024-congress-set-to-make-comeback-with-59-seats-bjp-gets-big-setback-with-23-seats-axis-my-india-prediction-latest-updates-2024-10-05-955675*
- Sharma, Rishab. (2024, October 06). Congress to reclaim Haryana, INDIA edge in J&K tight fight: Exit poll. *India Today.* https://www.indiatoday.in/elections/assembly/story/haryana-jammu-and-kashmir-assembly-election-2024-india-today-cvoter-exit-polls-result-congress-bjp-2611927-2024-10-05
- Sharma, Kritika. (2019, May 18). How the science of predicting an election has changed in India. *The Print*. https://theprint.in/india/how-the-science-of-predicting-an-election-has-changed-in-india/236392/
- Exit poll results of Haryana Assembly elections 2019. (2019, October 22). *The Times of India.* https://timesofindia.indiatimes.com/india/exit-poll-results-of-haryana-assembly-elections-2019/articleshow/71690151.cms
- Vasudev, Vikas. (2024, October 09). New candidates, caste coalitions help BJP beat anti-incumbency in Haryana. *The Hindu*.

♦♦♦♦♦

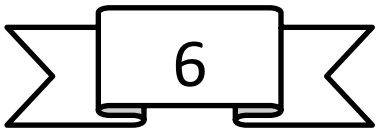

जम्मू कश्मीर के चुनावी राजनीति: एक अध्ययन

हिताक्षी गिल

विधार्थी, जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

जम्मू–कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक राज्य है, जिसका राजनीतिक परिदृश्य हमेशा से जटिल और बहुस्तरीय रहा है। इस क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर इतिहास, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, और भू–राजनीतिक कारक गहरा प्रभाव डालते हैं।

जम्मू और कश्मीर (J&K) हमेशा से भारत की राजनीति में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है, बल्कि इसका राजनीतिक इतिहास भी जटिल और चुनौतीपूर्ण रहा है। 2024 के चुनावों की तैयारी और संभावित परिदृश्य को देखते हुए, जम्मू–कश्मीर की राजनीति एक बार फिर चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

अनुच्छेद 370 का हटना जम्मू–कश्मीर की राजनीति का नया अध्याय है, लेकिन इसे स्थिरता और विकास की ओर ले जाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

शांति और प्रगति का द्वार लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनभागीदारी से खुलता है, विशेषकर जम्मू–कश्मीर में।

इतिहास की पृष्ठभूमि

जम्मू–कश्मीर का राजनीतिक इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ है। 1947 में भारत–पाकिस्तान विभाजन के समय, जम्मू–कश्मीर एक रियासत थी, जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। उन्होंने स्वतंत्र रहने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों के हमले के कारण, उन्होंने भारत के साथ विलय के लिए सहमति दी। इस समझौते के तहत, जम्मू–कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए के तहत संरक्षित किया गया।

राजनीतिक दलों की स्थिति

2024 के चुनावों में प्रमुख दलों की भूमिका और रणनीतियां निम्न प्रकार हैंः

1. नेशनल कांफ्रेंस (NC)

फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कांफ्रेंस अनुच्छेद 370 की बहाली को अपनी मुख्य मांग बना रही है। पार्टी का मानना है कि जम्मू–कश्मीर की स्वायत्तता ही क्षेत्र की समस्याओं का समाधान है।

2. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP)

महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली PDP ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना जारी रखी है। पार्टी की रणनीति केंद्र सरकार के खिलाफ स्थानीय मुद्दों को उठाने और जनता के असंतोष को भुनाने की है।

3. भारतीय जनता पार्टी (BJP)

BJP ने 2019 के फैसले के बाद जम्मू–कश्मीर में अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश की है। पार्टी का फोकस विकास, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई, और रोजगार सृजन पर है। इसके अलावा, BJP ने परिसीमन प्रक्रिया और नए मतदाताओं को लेकर अपनी रणनीति को तेज किया है।

4. कांग्रेस

कांग्रेस पारंपरिक रूप से जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रही है। हालांकि, पार्टी को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए नई रणनीतियों की जरूरत है।

5. गुप्कर गठबंधन (PAGD)

पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन, जिसमें NC, PDP और अन्य दल शामिल हैं, अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का दर्जा पुनर्स्थापित करने के लिए एकजुट हुए हैं। यह गठबंधन 2024 के चुनावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अनुच्छेद 370 और 35ए का हटना

5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 और 35ए को हटा दिया। इसके परिणामस्वरूप, जम्मू–कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। इस निर्णय को भारत के एकीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया गया, लेकिन इसने क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक तनाव को भी बढ़ा दिया।

वर्तमान राजनीतिक स्थिति

2019 के बाद जम्मू–कश्मीर की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया धीमी हो गई है। हालाँकि पंचायत और जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव कराए गए, लेकिन विधानसभा चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। इस वजह से जनता और स्थानीय राजनीतिक दलों में असंतोष है।

कश्मीर घाटी में राजनीतिक अस्थिरता और अलगाववादी गतिविधियाँ अभी भी चिंता का विषय हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और चीन की ओर से चुनौतियाँ भी जारी हैं।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

जम्मू–कश्मीर की राजनीति केवल सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा प्रभाव यहाँ के आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर भी पड़ता है।

1. बेरोजगारी

राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्षेत्र में निवेश और रोजगार सृजन बाधित हुआ है।

2. शिक्षा और स्वास्थ्य

संघर्ष और हिंसा के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

3. पर्यटन

यह क्षेत्र पर्यटन का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता के कारण पर्यटन उद्योग को गंभीर नुकसान हुआ है।

जम्मू और कश्मीर २०२४ का परिणाम

जम्मू–कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव को दर्शाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए कुल 49 सीटें जीतीं और पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गंदरबल और बडगाम जैसी प्रमुख सीटों पर जीत हासिल की। यह नतीजे NC के लिए उम्मीद से बेहतर रहे और उमर अब्दुल्ला ने इसे जनता के विश्वास का प्रमाण बताया।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 29 सीटें जीतीं और जम्मू क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखा। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) ने डोडा सीट जीतकर पहली बार जम्मू–कश्मीर विधानसभा में प्रवेश किया। पीडीपी ने इस चुनाव में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन किया, लेकिन पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने NC को उनकी जीत पर बधाई दी और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता जताई।

चुनाव परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां अभी भी जम्मू–कश्मीर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि स्थानीय मुद्दे और जनहितकारी नीतियां चुनावी परिणामों को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं।

निष्कर्ष

जम्मू–कश्मीर की राजनीति केवल क्षेत्रीय स्तर तक सीमित नहीं हैय यह भारत की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रणनीति का अहम हिस्सा है। 2019 के बाद से हुए बदलावों ने इस क्षेत्र को नए सिरे से परिभाषित किया है, लेकिन चुनौतियाँ अब भी बरकरार हैं। राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के माध्यम से ही जम्मू–कश्मीर को सही मायनों में भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सकता है।

इस क्षेत्र की राजनीति में सुधार के लिए न केवल केंद्र सरकार बल्कि क्षेत्रीय नेताओं और जनता को भी जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। शांतिपूर्ण और समृद्ध जम्मू–कश्मीर का सपना तभी साकार होगा, जब सभी पक्ष एकजुट होकर इस दिशा में कार्य करेंगे।

संदर्भ सूची

- बिकेश तिवारी. (2024) जम्मू–कश्मीर चुनाव में पॉकेट पॉलिटिक्स की श्सरहदेंश कितना तोड़ पाए सियासी दल? नतीजों से समझिए
- दीपक व्यास (2024) अब की बार अब्दुल्ला सरकार, जम्मू में बीजेपी का कायम रहा जलवा, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
- सुशील कुमार (2024) उमर सरकार में क्यों शामिल नहीं हुई कांग्रेस? महाराष्ट्र–झारखंड चुनाव को लेकर चला बड़ा दांव

♦♦♦♦♦

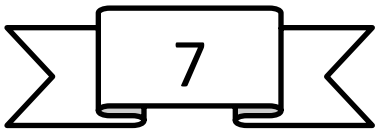

चुनाव विज्ञान बनाम चुनाव परिणामः हरियाणा एवं जम्मू–कश्मीर चुनाव विश्लेषण

आस्था सेहरावत

जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

परिचय

चुनाव पूर्वानुमान और चुनाव परिणाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दो परस्पर जुड़े हुए लेकिन अलग–अलग घटक हैं। चुनाव पूर्वानुमान, जिसमें चुनाव होने से पहले उसके परिणाम की भविष्यवाणी करना शामिल है, जनमत सर्वेक्षण, एग्जिट पोल, जनसांख्यिकीय विश्लेषण और सांख्यिकीय मॉडल जैसे विभिन्न तरीकों पर निर्भर करता है। इन पूर्वानुमानों को अक्सर राजनीतिक विश्लेषकों, मीडिया आउटलेट्स और अभियान रणनीतिकारों के लिए मूल्यवान उपकरण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे मतदाता व्यवहार, पार्टी की लोकप्रियता और संभावित चुनाव परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हालाँकि, पूर्वानुमान मतदाताओं के मूड और चुनाव से पहले के रुझानों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविक चुनाव परिणाम चुनाव के दिन मतदाताओं द्वारा किए गए वास्तविक विकल्पों से आकार लेते हैं। पूर्वानुमान में उपयोग किए जाने वाले परिष्कृत तरीकों के बावजूद, अक्सर पूर्वानुमानों और अंतिम परिणामों के बीच विसंगतियाँ होती हैं, जो मतदाता मतदान, क्षेत्रीय विविधताओं और अप्रत्याशित मुद्दों या घटनाओं के उद्भव जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं। इस प्रकार, चुनाव पूर्वानुमान और परिणामों के बीच परस्पर क्रिया अध्ययन का एक पेचीदा क्षेत्र बना हुआ है, जो लोकतांत्रिक परिणामों की भविष्यवाणी करने की शक्ति और सीमाओं दोनों को दर्शाता है।

2024 हरियाणा चुनाव–सामान्य अपेक्षाएँ

1. कृषि संकटः हरियाणा ने महत्वपूर्ण कृषि संकट का सामना किया है, विशेष रूप से फसल विफलता, ऋण और किसान विरोध जैसे मुद्दों से संबंधित। कृषि संकट को दूर करने, किसान

कल्याण को बढ़ाने और कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रभावी नीतियों की आवश्यकता चुनावों में एक केंद्रीय मुद्दा था।

2. जाति–आधारित राजनीतिः मतदाता व्यवहार अक्सर जातिगत निष्ठाओं को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल जाट समुदाय जैसे विशिष्ट समूहों को लक्षित करते हैं। आरक्षण और कल्याण कार्यक्रमों के संदर्भ में विभिन्न जातियों की चिंताओं को संबोधित करना चुनावों के दौरान एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी।

3. आर्थिक विकास और रोजगारः हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों, बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं की मांग बढ़ रही है। मतदाता यह मूल्यांकन करने के लिए उत्सुक थे कि कौन सी पार्टी आर्थिक विकास और रोजगार के वादों को पूरा कर सकती है, खासकर युवाओं के बीच।

4. कानून और व्यवस्थाः कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में, भी महत्वपूर्ण चिंताएँ थीं। मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की तलाश कर रहे थे जो सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार कर सकें।

हरियाणा के लिए पूर्वानुमान –

2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 2019 के चुनावों में उनके प्रदर्शन और केंद्रीय स्तर पर उनके नियंत्रण के आधार पर प्रमुख शक्ति के रूप में देखा गया था। चुनाव से पहले जनमत सर्वेक्षणों ने भविष्यवाणी की थी कि भाजपा पर्याप्त संख्या में सीटें हासिल करेगी, हालांकि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों से चुनौती मिलने की संभावना है।

सर्वेक्षणों ने खंडित जनादेश का अनुमान लगाया, जिसमें भाजपा को 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 40 से 50 सीटों के बीच जीतने की उम्मीद थी, जिससे वे सबसे बड़ी पार्टी बन गईं, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुमत के लिए पर्याप्त हों। मजबूत पारंपरिक समर्थन आधार वाली कांग्रेस को 30 से 35 सीटों के बीच सुरक्षित करने का अनुमान लगाया गया था, जबकि जननायक जनता पार्टी को संभावित किंगमेकर के रूप में देखा गया था, जिसमें उन्हें लगभग 10 से 12 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की गई थी।इंडियन नेशनल लोकदल और निर्दलीय जैसे अन्य छोटे दलों की न्यूनतम भूमिका होने की उम्मीद थी।

हरियाणा चुनाव 2024 के वास्तविक परिणाम

2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतिम परिणाम में, भाजपा 47 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने राज्य में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उच्च स्तर के समर्थन के बावजूद, केवल 24 सीटें जीत पाई, जो उम्मीदों से बहुत कम है। जननायक जनता पार्टी 12 सीटें जीतने में सफल रही, जिसने राज्य में एक प्रमुख क्षेत्रीय ताकत के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य सहित छोटी पार्टियों का प्रतिनिधित्व न्यूनतम था।

परिणाम के पीछे मुख्य कारकः

- भाजपा का वोट शेयर मजबूत हुआ
- जाति आधारित वोटिंग मजबूत हुई
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,की गिरावट
- क्षेत्रीय दलों का प्रभाव

2024 जम्मू और कश्मीर चुनावः सामान्य अपेक्षाएँ –

1. अनुच्छेद 370 के बाद राजनीतिक अनिश्चितताः 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल–पुथल का अनुभव हुआ। स्थिरता, शासन और एक स्पष्ट राजनीतिक दिशा की आवश्यकता एक प्रमुख चिंता थी। मतदाताओं ने उन दलों और नेताओं की तलाश की जो इन चिंताओं को दूर कर सकें और क्षेत्र में शांति और विकास ला सकें।

2. सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबलाः सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही, विशेष रूप से कश्मीर घाटी में, जो उग्रवाद और सीमा पार तनाव से प्रभावित रही है। शांति, सुरक्षा और हिंसा में कमी के लिए मतदाताओं की आवश्यकता ने मतदान पैटर्न को प्रभावित किया, जिसमें कई उम्मीदवारों ने ऐसे उम्मीदवारों का पक्ष लिया जो स्थिरता सुनिश्चित कर सकें।

3. विकास और आर्थिक विकासः मतदाताओं ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और नौकरी के अवसरों में सुधार की मांग की, जिन्हें क्षेत्र की वसूली और विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया।

4. पहचान और स्वायत्तता की चिंताएँः कई मतदाताओं ने, विशेष रूप से कश्मीर घाटी में, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद स्वायत्तता और क्षेत्र की विशिष्ट पहचान के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।

5. युवा जुड़ाव और रोजगारः जम्मू और कश्मीर की युवा आबादी, जो राजनीतिक स्थिति से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, को बेहतर रोजगार के अवसरों, शिक्षा और सामाजिक कल्याण की महत्वपूर्ण उम्मीदें थीं। चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण माना गया।

जम्मू और कश्मीर के लिए पूर्वानुमान

जम्मू और कश्मीर में, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद के परिदृश्य ने एक नया और अप्रत्याशित राजनीतिक माहौल बनाया। इस क्षेत्र में काफी अनिश्चितता देखी गई, खासकर एनसी और पीडीपी जैसी प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों की अनुपस्थिति में, जिन्हें या तो दरकिनार कर दिया गया या उन्हें नई वास्तविकताओं के अनुकूल होना पड़ा। भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को प्राथमिक दावेदार के रूप में देखा गया, हालांकि छोटी स्थानीय पार्टियाँ विशिष्ट क्षेत्रों में परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं।

पूर्वानुमान मॉडल ने भविष्यवाणी की कि भाजपा जम्मू क्षेत्र में अपना गढ़ बनाए रखेगी, जबकि कश्मीर घाटी के विभाजित रहने की उम्मीद है, स्थानीय दलों को अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जनमत सर्वेक्षणों ने सुझाव दिया कि भाजपा 90 सदस्यीय जम्मू और कश्मीर विधानसभा में से लगभग 60 से 65 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस और छोटे क्षेत्रीय दलों को संयुक्त रूप से लगभग 15 से 25 सीटें जीतने की उम्मीद थी।

जम्मू और कश्मीर चुनाव 2024 के वास्तविक परिणाम

2024 के जम्मू और कश्मीर चुनाव में, भाजपा ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया, जम्मू क्षेत्र में महत्वपूर्ण संख्या में सीटें जीतीं। पार्टी 55 सीटें हासिल करने में सफल रही, जो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हालांकि, कांग्रेस और अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों ने पूवानुमान के अनुसार खराब प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने 18 सीटें जीतीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), राजनीतिक उथल–पुथल के बावजूद, कश्मीर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने में सफल रही, उसने 10 सीटें हासिल कीं।

परिणाम के पीछे मुख्य कारक

- जम्मू में भाजपा का गढ़
- ध्रुवीकरण
- क्षेत्रीय दलों का संघर्ष
- स्थानीय और छोटी पार्टियों का प्रभाव

चुनाव परिणाम –

हरियाणा और जम्मू–कश्मीर दोनों में इन विविध मुद्दों को संबोधित करने के लिए सूक्ष्म राजनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, जिससे दोनों राज्यों में चुनाव स्थानीय जरूरतों और चिंताओं का प्रतिबिंब बन गए, जिसमें आर्थिक विकास और सुरक्षा से लेकर राजनीतिक स्थिरता और पहचान संरक्षण तक शामिल है। जम्मू और कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के परिणाम – 2024 के आम चुनावों के बाद चुनाव कराने वाले पहले राज्य – कुछ हद तक अप्रत्याशित थे। जम्मू और कश्मीर में, जहां 2019 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद पहली बार चुनाव हुए थे, कुछ लोगों ने त्रिशंकु विधानसभा को उम्मीद की थी। हरियाणा में, कई लोगों का मानना था कि दो बार की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार वोट से बाहर हो जाएगी। दोनों में से कोई भी परिदृश्य नहीं बना, नेशनल कांफ्रेंस (एनसी)–कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू–कश्मीर में काफी आसानी से जीत हासिल की तथा भाजपा ने हरियाणा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया।

निष्कर्ष

हरियाणा और जम्मू–कश्मीर में 2024 के चुनाव चुनाव पूर्वानुमान की चुनौतियों और सीमाओं को उजागर करते हैं। हालांकि परिणाम मोटे तौर पर कुछ पूर्वानुमानित रुझानों के अनुरूप थे, लेकिन कई प्रमुख आश्चर्य सामने आए, खासकर क्षेत्रीय दलों के प्रदर्शन और भाजपा की अपने आधार को मजबूत करने की क्षमता के संदर्भ में।

हरियाणा में, पूर्वानुमान मॉडल ने भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करने के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि उन्होंने पार्टी की ताकत और कांग्रेस की गिरावट को कम करके आंका। जम्मू और कश्मीर में, जम्मू क्षेत्र में भाजपा का प्रभुत्व अपेक्षित था, लेकिन कश्मीर क्षेत्र में राजनीतिक विखंडन अनुमान से कहीं अधिक स्पष्ट था, जो दर्शाता है कि क्षेत्रीय कारक और सुरक्षा मुद्दे जटिल

तरीकों से मतदाता व्यवहार को आकार देते रहते हैं। राजनीतिक गतिशीलता कई अप्रत्याशित कारकों से आकार लेती है, जिसमें अंतिम समय में अभियान में बदलाव से लेकर अचानक राजनीतिक घटनाक्रम शामिल हैं, जो परिणामों की सटीकता के साथ भविष्यवाणी करने में कठिनाई को उजागर करते हैं।

संदर्भ सूची

- www.isas.nus.edu.sg
- www.eco.gov.in
- times of india.indiatimes.com

♦♦♦♦♦

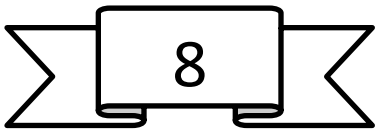

महिलाओं की चुनावी राजनीति में बढ़ती भूमिका

एलिन

विद्यार्थी, जीसस एंड मेरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

'नारी' तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग में।

पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।।

महिलाओं की राजनीति में बढ़ती भूमिका आज के योग में एक महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को न केवल मजबूती प्रदान करती है, बल्कि समाज को अधिक समावेशी व प्रगतिशील बनाने में भी सहायक होती है। महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणा को मजबूत करती है, जिसमें हर वर्ग और समुदाय की आवाज को समान रूप से सुना और महत्त्व दिया जाता है। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने साथ साथ समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की भी सुनिश्चित करती है। राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका यह दर्शाती है कि समाज प्रगति और बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की इस क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, वह न केवल उत्साहजनक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि महिलाएं अब नेतृत्व की भूमिका में अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रहो हैं। उनकी स्थिति नीति–निर्माण, सामाजिक सुधार और समग्र विकास को गति देने में अहम योगदान दे रही है। महिलाओं के राजनीति में सक्रिय होना केवल एक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन है जो समाज के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

महिलाओं की चुनावी राजनीति में बढ़ती भूमिका के कारण

महिलाओं की राजनीति में बढ़ती भूमिका के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहले, महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि ने उन्हें राजनीतिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा के प्रति सचेत किया है। इसके साथ ही, कानूनी और संवैधानिक सुधार, जैसे पंचायत राज संस्थाओं में

महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और हरियाणा में 50% आरक्षण की पहल, ने उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है। सामाजिक परिवर्तनों, जैसे परंपरागत सोच में बदलाव और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता व स्वरोजगार के अवसरों में सुधार, ने भी उनके नेतृत्व को प्रोत्साहित किया है। महिला नेताओं जैसे इंदिरा गाँधी और प्रतिभा पाटिल के प्रेरणादायक उदाहरणों ने जो क्षेत्रीय स्तर पर भी महिला नेतृत्व को उभरने में मदद की है। इन सभी कारणों ने महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है।

महिलाओं की राजनीति में योगदान

महिलाओं का राजनीति में योगदान समाज के विकास और उनके सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। वे नीतियों और योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रही है। सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनहित के मुद्दों पर उनका विशेष ध्यान समाज को प्रगतिशील और समावेशी बना रहा है। राजनीति न केवल महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में लाने का अवसर दे रही है, बल्कि यह उनकी सशक्तिकरण और विकास का एक महत्वपूर्ण साधन भी बन गई है। गांव, पंचायत और नगर पालिकाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं, जिससे वे अपनी स्थिति मजबूत करने के साथ साथ समाज में लैंगिग समानता और नहीं आये की दिशा में भी योगदान दे रही है। उनकी सक्रियता ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक व्यापक और लोकतांत्रिक बताया है, जिससे समाज के सभो वर्गों को लाभ मिल रहा है।

हरियाणा के संदर्भ में महिलाओं की राजनीति में भूमिका

हरियाणा में महिलाओं की राजनीति में भूमिका का इतिहास समय के साथ गहराई और विस्तार प्राप्तकर्ता गया है। शुरुआत में, महिलाओं की भागीदारी केवल सीमित और पारंपरिक थी, जहाँ वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों से लगभग दूर रही। यह स्थिति मुख्य रूप से पित्र सत्तात्मक समाज और लैंगिक असमानता इसके कारण बनी रही। हालांकि, समय के साथ हरियाणा में पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण की पहल और शिक्षा तथा जागरूकता अभियान ओने एक बड़ा बदलाव लाया। पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण ने महिलाओं को न केवल स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का मौका दिया, बल्कि उनके आत्मविश्वास और राजनीतिक क्षमता को भी बढ़ावा दिया। अब हरियाणा की महिलाएं न केवल पंचायतों में, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज कर रही है। यह बदलाव महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा के

प्रशासक, आर्थिक स्वतंत्रता और परंपरागत सोच में सुधार का परिणाम है। हरियाणा की महिलाएं आज सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित कर रही है और उनकी बढ़ती भागीदारी समाज और लोकतंत्र को अधिक समावेशी और प्रगतिशील बना रही है।

महिला आरक्षण और उसकी प्रभावशीलता

पंचायतराज संस्थाओं में 50% महिला आरक्षण, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। इस नीती का उद्देश्य है महिलाओं को जमीनी स्तर पर निर्णय लेने में भागीदार बनाना। हरियाणा की 6227 पंचायतों में लाखों महिलाएं सरपंच, पंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति की सदस्य बनीं। यह आरक्षण उन्हें समाजिक बाधाओं से ऊपर उठने का अवसर देता है। हरियाणा जैसे राज्य में, जहाँ लैंगिक असमानता एक बड़ा मुद्दा है, यह कदम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनकी आवाज को सुने जाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

राजनीति में महिलाओं की नई पहचान और अवसर, हरियाणा में महिला आरक्षण ने महिलाओं को राजनीतिक पहचान बनाने और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। आंकड़ों के अनुसार, 2016 में हुए पंचायत चुनाव में 42% से अधिक महिलाओं ने भाग लिया।, इन महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के लिए, कई महिला सरपंचों ने अपने गांव में स्वच्छता और बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति सोच में भी बदलाव आया। इसने राजनीति में महिलाओं की सशक्त भूमिका को और मजबूत किया।

महिला नेताओं के उदाहरण

सुधा चौधरी (प्रभावी महिला सरपंच), सुधा चौधरी जैसी महिला सरपंचों ने पंचायतीराज में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, महिला स्वच्छता, ओर बालिका सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी योजनाओं से स्थानीय स्तर पर समाज में बदलाव लाने में मदद की है।

कमला देवी, इन्होंने सरपंच के रूप में ना केवल विकास कार्यों को बढ़ावा दिया बल्कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने की दिशा में भी कार्य किए। उनके नेतृत्व में कई गांवों में स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण जैसे कार्य सफल हुए।

सुमित्रा देवी, यह है महिला आरक्षण का लाभ उठाकर सरपंच बनीं और अपने गांव में बालिका शिक्षा और महिला सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कार्यों ने यह साबित किया कि महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता और वे समाज में बदलाव ला सकती हैं।

बिमला चौधरी (पंचायत सदस्य), हरियाणा की पंचायत सदस्य बिमला चौधरी ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महिलाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएं और सरकारी योजनाओं को प्रभावी तरीक से लागू किया।

इन महिलाओं ने हरियाणा में नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके कार्य अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

चुनौतियां और आगे का रास्ता

सबसे बड़ी चुनौती पित्र सत्तात्मक समाज और रूढ़ीवादी सोच है, जो महिलाओं के नेतृत्व में बाधा डालती है। इसके अलावा, राजनीतिक निर्णयों मैं महिलाओं को सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है। इस समस्या का समाधान शिक्षा और परीक्षण कार्यक्रम ओके माध्यम से किया जाता है, ताकि महिलाओं को नेतृत्व के लिये बेहतर कौशल और आत्मविश्वास मिल सके। इसके साथ ही, महिलाओं को सशक्त बनाने वाली नीतियों का कार्यान्वयन आवश्यक है, ताकि फिर राजनीति और समाज में अपनी भूमिका निभा सके। यह छवि दिखाती है कि चुनौतियों के बावजूद महिला का नेतृत्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का हिस्सा बन सकता है।

महिलाओं की राजनीति में बढ़ती भागीदारी समाज और राष्ट्र के लिए सकारात्मक संदेश है। यह न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के दृ ष्टिकोण को शामिल कर शासन को अधिक समावेशी बनाती है। आधुनिक युग में स्त्रियाँ सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं सहायक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान कार्य करने लगी है। इनमें विजयलक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गाँधी, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

हरियाणा जैसे राज्यों में महिला आरक्षण के ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के राजनीति नहीं सशक्त किया है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है इसके साथ वे समाज और विकास की मुख्यधारा में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

संदर्भ सूची

- https://www.hindikunj.com/2024/03/bhartiya-rajniti-mein-mahilaon-ki-bhumika.html?m=1
- https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/political-activeness-of-indian-women
- https://www.downtoearth.org.in/amp/story/governance/ground-report-50-reservation-in-panchayat-a-starting-point-for-haryana-women-85786
- https://nimd.org/what-we-do/womens-political-participation/

♦♦♦♦♦

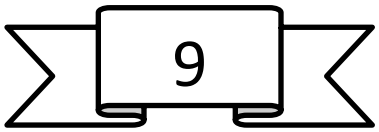

चुनाव विज्ञान बनाम चुनाव परिणामः पूर्वानुमान या यथार्थता?

हितेन्द्र बारगल

सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, गुनौर (म.प्र.)

प्रियंका बारगल

शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, (म.प्र.)

चुन चुन के करो अपना मत चयन।

ना की सुन सुन के।।

रहो एक ही नाव में सवार।

क्योंकि भ्रमित व्यक्ति रहेगा हमेशा देश पर भार।।

भारत जैसे लोकतांत्रिक, गरीब, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम देश में, सही प्रतिनिधित्व के चुनाव हेतु संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना की गई, जो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, किन्तु देश में जहां आय की असमानता तथा अन्य सामाजिक ,आर्थिक एवं राजनैतिक कारणों से धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में ही सकेंद्रित हो जाता है वही, यही तथाकथित वर्ग बाहुबल, पैसों की ताकत पर चुनाव के परिणाम को भी परिवर्तित रखने की ताकत रखता है।

कुछ उम्मीदवार हो सकता है कि बाहुबल या पैसों के बल पर चुनाव जीत भी जाते हो, पर चुनाव का अंतिम परिणाम अभी भी बहुत हद तक आम लोगों की इच्छा पर ही निर्भर करता है,वहीँ कई

जगह अभी भी परिवारवाद ही चल रहा है तथा भाई भतीजे वाद का भी बोलबाला है,जो चुनाव विज्ञान के क्षेत्र में नकारात्मक भूमिका निभाता है।

हमारे देश में चुनाव को त्यौहार जैसा मनाया जाता है, पुरे साल किसी न किसी राज्य में चुनाव या उपचुनाव होते ही रहते है। चुनावी कुरुक्षेत्र में कौन किसे हराता है? कौन पांच सालों के लिए विजयी ताज पहनता है? इसका फैसला अंत में जनता जनार्दन द्वारा ही किया जाता है।

अभी हाल ही में हरियाणा व जम्मू–कश्मीर में 90–90 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो गए है।

हरियाणा चुनाव के संकल्प पत्र में अगर हम मुख्य बिंदु देखें तो वो है "गरीब, किसान,पहलवान, और नौजवान" इन चारों वर्गों पर ही वर्तमान सत्तारूढ़ दल तथा विपक्ष का पूरा तामोरदार दिखाई पड़ता हैद्य हरियाणा में वैसे भी देखे तो तीन चीजों की प्रमुखता है वहाँ का प्रसिद्ध नारा ही है दृ "जय जवान जय किसान और जय पहलवान" इसीलिए जवान के लिए अग्नि वीर योजना, किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, तथा पहलवान की बात करे तो जहाँ भाजपा नेता बृजभूषणशरण सिंह का मामला खटाई में है, वही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में अच्छी शिक्षा, रोजगार, वंचितों को प्लॉट, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं को ₹2000 भत्ते के साथ "सात वादे पक्के इरादे" नाम से अपना संकल्प पत्र जारी किया, वहीं भाजपा ने महिलाओं के लिए 2100 भत्ता, अग्निवीर को नौकरी की गारंटी, के साथ ही 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त लगभग 20 वादे किए हैं।

हरियाणा में अग्नि वीर योजना और दूसरा बिना पर्चे बिना खर्च की सरकारी नौकरी और तीसरा पहलवान के बल पर सारा खेल रच दिया गया था। अग्नि वीर योजना में भाजपा ने पेंशन को शामिल कर तुरुप का इक्का डाल दिया है,वही इस योजना का कार्यकाल बढाकर लोलीपॉप भी दे दी है, भाजपा द्वारा बिना पर्ची दृखर्ची यानी बिना सिफारिश और रिश्वत वाली सरकारी नौकरी से राज्य को मुक्त किए जाने का दावा भी कारगार रहा द्य हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपना खाता खुलवाने में असफल रही उसने 88 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे पर कोई भी जीत नहीं सका।

जम्मू कश्मीर की बात करे तो, जम्मू कश्मीर में कुल आबादी में लगभग 60% मुसलमान तथा लगभग 28% हिंदू है अगर जम्मू– कश्मीर में सत्ता के करीब पहुंचना है तो वहां जम्मू के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है।

जम्मू–कश्मीर हेतु बीजेपी के संकल्प पत्र में जहां 25 गारंटी दी गई है संकल्प पत्र में आतंकवाद पर कड़े प्रहार की बात कही गई है, परिवार की वरिष्ठ महिला को सालाना ₹10000 का वादा ,उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को दो सिलेंडर मुफ्त, युवाओं के लिए भी रोजगार योजना, जम्मू कश्मीर में डल झील के साथ टूरिज्म विकास , मेट्रो ट्रेन, सौ मंदिरों का विकास, किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाना, कश्मीरी प्रवासी पंडितों की वापसी जैसे लुभावने विचार दिए गए है, वहीं कांग्रेस ने पहले 100 दिन में अल्पसंख्यक आयोग के गठन, सभी फसलों का सौ परसेंट बीमा, सेब के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, अल्पसंख्यक एवं लोकायुक्त आयोग का गठन, बेरोजगारों के लिए 3500 भत्ता, महिला सशक्तिकरण योजना, मुफ्त राशन को 5 किलो से बढाकर 11 किलो किया गया ,कश्मीर हिंदूओं के लिए मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए पुनर्वास कार्यक्रम को पूरी तरह लागू करने, विस्थापित कश्मीरी हिंदू समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी व पुनर्वास के साथ पंजाबी भाषा को भी सम्मान दिए जाने का कहा गया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर पाकिस्तान तो बहुत ही खुश हुआ है।

जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का गठबंधन जीता है, जिसने यह दर्शा दिया की सत्तारूढ़ दल द्वारा 5 अगस्त 2019 को किया गया फैसला सर्वदा गलत था। जम्मू कश्मीर में 5 साल बाद भाजपा ने 48 सीटों से जहां बहुमत हासिल किया वहीं, हरियाणा में उसने हैट्रिक बना ली है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35–अ खत्म होने के बाद पहली बार चुनाव संपन्न कराए गए हैं। भाजपा को जम्मू में तो सफलता मिली पर कश्मीर में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा।

भाजपा भले ही जम्मू–कश्मीर में सरकार नहीं बना पाई, पर उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वह क्या कर सकती है, पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव पर केंद्रित थी।

हम चुनाव के परिणामो का निश्चित फल देखे तो ,चुनाव विश्लेषण का कोई सटीक सामान्य नियम नहीं है। कई बार एक्जिट पोल के परिणाम भी पूरी तरह से गलत साबित हो जाते हैं,

एग्जिट पोल जिस दल को जीता रहे होते हैं वहीं कई बार बहुत अधिक वोटो के अंतर से हार जाता है, वैसे भी आजकल मीडिया सिर्फ नाम का ही चौथा स्तंभ रह गया है, कई मायनों में मीडिया द्वारा पैसा लेकर वही खबर दिखाई जाती है जो या तो सत्ता पक्ष दिखाना चाहता ह या विपक्षी दल द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित या साबित करने हेतु दिखलाई जाती है।

जम्मू कश्मीर चुनाव में किसी नेता के द्वारा कहा भी गया था की वे टीवी चौनल तथा एग्जिट पोल को लेकर परेशान नहीं है वे टीवी चौनल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आदि पर होने वाले सभी शोरगुल को नजर अंदाज कर रहे हैं।

आज की जनता जनार्दन को भी पहले जैसा बेवकूफ समझना अपने आप को ही बेवकूफ बनाने जैसा है। आज की समझदार जनता हर दल से पैसा, उपहार लेकर किसी तीसरे दल को, जिनके संकल्प पत्र में सही व सार्थक बात लिखी रहती है , उसी को ही वोट देना पसंद करती हैं। बहुत ही नीचे तबके के गरीब, अनपढ़ लोगों की बात छोड़ दी जाए तो आज देश की लगभग 65% से ज्यादा आबादी युवा है, तथा संचार साधनों का सही उपयोग करना जानती है अतः आज की युवा आबादी को फालतू के प्रलोभनों ध्रपंचों में उलझाना आसान नहीं है। आज की युवा पीढ़ी वर्तमान के साथ–साथ भविष्य का भी भला करना अच्छे से जानती है, पर युवा पीढ़ी को भी अपने कर्तव्यों का भली– भांति निर्वहन करना होगा, नहीं तो देश की स्थिति उस गांव जैसी हो जाएगी, जहां के राजा ने कहा था की अकालग्रस्त गाँव की भलाई के लिए, रात भर सारे नागरिक कुएं में एक लोटा दूध डाले तो गांव में बारिश हो जाएगी और वहां की जनता यही सोचते हुए सोई रह गई कि मेरे एक लोटे से क्या फर्क पड़ जायेगा? बाकी तो सभी पानी डाल ही रहे हैं और वह कुआं सुबह तक सुखा का सुखा ही रह गया।

इसी प्रकार आम जनता को भी अपने देश की भलाई को सर्वोपरि रखते हुए बिना किसी के बहकावे में आए, पैसो या अन्य वस्तु का लालच किए बिना सोच समझकर अपने अमूल्य मत का प्रयोग करना चाहिए और इसमें मिडिया को भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से बिना भेदभाव के निभाना चाहिए, किसी भी चुनाव के विश्लेषण में मिडिया भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं।, मीडियाकर्मियों को आम जनता को चुनाव का सटीक विश्लेषण उपलब्ध करवाना चाहिए ,पर असल में मीडिया द्वारा किसी उम्मीदवार के तारीफ के फूल बांध दिए जाते हैं तथा किसी और उम्मीदवार को पूरी तरह से भ्रष्टाचारी घोषित करार कर दिया जाता है, पर असल में कोई भी उम्मीदवार न तो पूरी तरह से ईमानदार होता है न ही पूरी तरह से बेईमान, पर मिडिया द्वारा दिखाई गई खबरों से मतदाताओं की मनोवृत्ति पर व्यापक प्रभाव पड़ता हैद्य

एक राज्य के चुनाव परिणाम आने के पश्चात् ही कुछ समय के अंतराल के पश्चात् दुसरे राज्यों में भी चुनाव हो सकते है ,जैसे अभी जम्मू कश्मीर के बाद, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, आम जनता में कही न कही दुसरे राज्यों के परिणामों का भी असर पड़ता ही है।

कहां भी जाता है जो दिखता है, वही बिकता है हमारे देश की कुछ अनपढ़ आबादी को तो बस चुनाव चिन्ह दिखा कर भेज दिया जाता है, उन्हें ना तो अपने भले बुरे की पहचान होती है और न ही अपने देश के विकास से मतलब होता है मीडिया द्वारा प्रसारित तस्वीरों से भी चुनाव परिणाम पर बहुत खराब या अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है।

वर्तमान में भारत में "एक देश एक चुनाव" की और कदम बढायें जा रहे है, अगर यह नीति सफलतापूर्वक लागु हो जाती है, तो बिना किसी भेदभाव के और चालाकी के देश में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न किये जा सकेंगे ,जिससे अनावश्यक खर्चे में भी कटौती होगी तथा इस बचे हुए धन का उपयोग देश के विकास में किया जा सकेगा।

टिप्पणी

इंडिया गठबंधन

भारत की सबसे बडी विपक्ष की पार्टी जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में 26 राजनीतिक दलों का एक बहुत बड़ा गठबंधन हुआ है, यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में गठित किया गया है।

चुनाव धांधली

चुनाव में अपने वोट तथा जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़।

निर्वाचन क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्र में एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता आते है, जो अपने क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि को चुनते हैं।

संदर्भ सूची

- https://ndtv.in/india/election-results-2024-haryana-jammu-kashmir-chunav-results-bjp-congress-vidhan-sabha-chunav-results-6736229
- https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/haryana-jk-vidhan-sabha-result-2024-date-vote-count-time-check-latest-updates-1728328926-2.
- https://www-nature-com.translate.goog/articles/d41586-024-00956-

♦♦♦♦♦

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281